PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 258 ● भिलाई, गुरुवार 23 अप्रैल 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

बंगाल में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी कांग्रेस

ममता दीदी की विदाई की तिथि 4 मई–अमित शाह

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दम दम उत्तर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों पर बरसे। शाह ने दावा किया कि इस बार बंगाल से ममता दीदी की विदाई हो जाएगी। अमित शाह ने इस दौरान पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। साथ ही मल्लिकार्जुन खरगे को पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी घेरा। अमित शाह ने कहा, 4 मई को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 9 बजे पहला राउंड आएगा, दोपहर 1 बजे तक गिनती समाप्त होते-होते ममता दीदी का टाटा-बाय-बाय हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम मोदी पर दिए बयान पर पलटवार किया है. अमित शाह ने कहा कि खरगे पहले इस तरह के बयान नहीं देते थे. लेकिन, राहुल बाबा के साथ रह कर उनकी भाषा भी बिगड़ने लगी है. राहुल के साथ रहने का ही असर है जो कांग्रेस अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी कह रहे हैं.गृह मंत्री अमित शाह ने आज दम दम उत्तर विधानसभा में जनसभा की। अमित शाह ने कहा, 4 मई को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। 9 बजे पहला राउंड आएगा, 10 बजे दूसरा राउंड आएगा, और दोपहर 1 बजे तक गिनती समाप्त होते-होते ममता

दीदी का टाटा-बाय-बाय हो जाएगा। 29 तारीख को आप सभी को वोट डालना है, लेकिन किसी को विधायक या भाजपा सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाने के लिए वोट डालना है।नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। राहुल बाबा के साथ रह रह कर खरगे जी की भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी जितना गाली दोगे, जितना कीचड़ गिराओगे, कमल उतनी शान से खिलेगा।भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को निर्वाचन आयोग पहुंचा और उसने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की आतंकवादी संबंधी टिप्पणी के लिए उनके (खरगे) खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में निर्मला सीतारमण समेत तीन केंद्रीय मंत्री शामिल थे।निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनावी राज्य तमिलनाडु में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खरगे ने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा जो अत्यंत निंदनीय है। सीतारमण ने कहा, यह भारत की जनता द्वारा दिए गए (प्रधानमंत्री मोदी को) जनादेश का अपमान है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पूरी तरह से हताश है।

बंगाल की पहचान से नहीं होगा खिलवाड़- योगी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा के प्रचार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोरासांको विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोलकाता के मेयर के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें उर्दू के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की पहचान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बंगाल की पहचान काबा से नहीं, बल्कि मां कालीबाड़ी से जुड़ी रही है। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर भी सवाल उठाए। योगी ने कहा कि बंगाल में अव्यवस्था का माहौल वैसा ही है जैसा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में था।

संक्षिप्त समाचार

15000 का इनामी शातिर बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

नईदिल्ली। दिल्ली पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी यूपी के बुलंदशहर से वांछित था और दिल्ली के आस्था कुंज पार्क, अमर कॉलोनी क्षेत्र में एक गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया। सूत्रों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर, एटीएफ/एसईडी की टीम ने 20 अप्रैल को तत्काल कार्रवाई करते हुए इलाके में जाल बिछाया। सूचना थी कि एक शातिर और इनामी अपराधी उस क्षेत्र में आने वाला है। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी की। जैसे ही आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया, उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सफलतापूर्वक काबू कर लिया।

अब बालू तस्करी मामले में कोलकाता पुलिस के डीसी शांतनु सिंह बिस्वास को ईडी का समन

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिंह बिस्वास को अब बालू तस्करी मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे पहले एजेंसी उन्हें जमीन भ्रष्टाचार मामले में भी समन भेज चुकी है। सूत्रों के अनुसार, शांतनु सिंह बिस्वास को आज यानी पहले चरण के मतदान के दिन, सॉल्टलेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होने को कहा गया है। इसी मामले में झाड़ग्राम के पूर्व जिलाधिकारी सुनील अग्रवाल को भी समन जारी किया गया है। हाल के दिनों में प्रवर्तन निदेशालय ने बालू तस्करी मामले की जांच के सिलसिले में राज्य के विभिन्न जिलों में कई छापेमारी अभियान चलाए हैं। हालांकि, शांतनु सिंह बिस्वास और सुनील अग्रवाल को किस विशेष परिस्थितियों में तलब किया गया है, यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। इस बीच एक अलग मामले में बेहाला के कारोबारी जय कामदार के साथ शांतनु सिंह बिस्वास और उनके परिवार के संबंधों का दावा भी जांच एजेंसी ने किया है। एजेंसी का आरोप है कि प्रभाव का इस्तेमाल कर कारोबारी को जमीन दिलाने में मदद की जाती थी।

बालेन शाह सरकार बनने के बाद से ही विवादों में

बालेन पर करप्शन का आरोप गृहमंत्री सुदन गुरुंग का इस्तीफा

नेपाल/ एजेंसी

नेपाल की बालेन शाह सरकार बनने के बाद से ही विवादों में है। अपने कई फैसलों को लेकर बालेन सरकार को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। छात्र संघ प्रतिबंध करने और भारत से लाने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के कारण लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बालेन शाह सरकार नये विवाद में फंस गई है। भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर सत्ता में आने वाली नेपाल की बालेन शाह सरकार पर करप्शन के आरोप लगे हैं। तीन हफ्ते में ही नेपाल के गृहमंत्री सुदन गुरुंग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बाद गुरुंग

ने अपना इस्तीफा पीएम बालेन शाह को सौंप दिया है। सुदन गुरुंग 'जेन-जी क्रांति' से राजनीति में आए थे। सुधन गुरुंग ने गृहमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था। हालांकि अब सुदन गुरुंग पर आय से अधिक संपत्ति से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक कई तरह के आरोप लगे हैं। सुधन गुरुंग पर विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्टा के साथ व्यापारिक हिस्सेदारी और माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों में शेयर खरीदने आरोप लगे हैं।फेसबुक पोस्ट में सुधन गुरुंग ने लिखा-मुझसे जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और पदों पर रहते हुए हितों के टकराव से बचने और जांच प्रक्रिया पर किसी भी तरह के प्रभाव से बचने के लिए मैंने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने आगे लिखा कि- मेरे लिए नैतिकता पद से ऊपर है और जनता के विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं है। नेपाल में चल रहे लद्दू' आंदोलन, जो सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है।

राप्ती नदी में दो बच्चियों की डूबने से मौत

श्रावस्ती। थाना सोनवा क्षेत्र अन्तर्गत राप्ती नदी में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। नहाते समय पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार थाना सोनवानी क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी धर्मराज की 11 वर्षीय बेटी अंशिका और छोटकर की 13 वर्षीय बेटी गुलशन मंगलवार दोपहर घर के पास टहलते हुए राप्ती नदी के किनारे पहुंच गईं। गांव से लगभग 500 मीटर दूर बह रही नदी में दोनों बच्चियां नहाने के लिए उतर गईं। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वे गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं।

30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र!

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के खिलाफ लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव,कांग्रेस ने सत्र के औचित्य पर उठाए गए सवाल.......

रायपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा से पारित नहीं हो पाने पर 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहुत किया जा रहा है. सत्र के दौरान अधिनियम के पारित नहीं होने पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा. विधानसभा के विशेष सत्र की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सरकार की ओर से 30 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित करने का आग्रह हुआ. विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि कितने दिन का सत्र होगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आधी आबादी को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि उनके अधिकार दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा.वहीं उप मुख्यमंत्री साव ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने पर कहा कि कांग्रेस घटिया और निम्न स्तर की राजनीति कर रही है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह की भाषा का उपयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है. कांग्रेस अपनी गिरती हुई राजनीति का परिचय दे रही है.अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया. ऐसे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के राजनीतिक पतन और घटियापन को दर्शाता है. सचिन तेंदुलकर के बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सुरक्षा सवालों पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नक्सलवाद खत्म हो.

पीएम मोदी को कहा था आतंकवादी

खड़गे से अब इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब

नई दिल्ली। तमिलनाडु चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। भाजपा ने इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग से मांग की थी कि इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाए। इसको लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसको गंभीरता से लेते हुए बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे को एक सख्त नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले में 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को तमिलनाडु में एक प्रेस

कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें 'आतंकवादी' कह दिया था। खड़गे ने अन्नादुरई के सिद्धांतों का हवाला देते हुए डीएमके के भाजपा के साथ गठबंधन पर सवाल उठाए और कहा कि वे मोदी के साथ कैसे जा सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं।

ट्रक ट्रेलर की टक्कर में दो की मौत एक गंभीर

जौनपुर। बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर नेशनल हाइवे 731 पर ट्रक ट्रेलर की टक्कर में जहां दो. लोगों की मौत हो गयी वहीं एक गंभीर घायल हो गया है। बताते है कि मंगल वार की सुबह ट्रक संख्यासुल्तानपुर से आलू लादकर वाराणसी जा रही थी। ज्योंही बदलापुर के सरोखनपुर स्थित हाइवे पर पहुंची ही थी कि ट्रेलर संख्यात्र.52. व्व. 2322 से भिड़ंत हो गया। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस व एन एच की पेट्रोलिंग टीम ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने राम करन गुर्जर निवासी जयपुर व एक अन्य को मृत घोषित कर दिया।

होर्मुज में कोहराम

गुजरात आ रहे जहाज पर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का हमला,कब्जे में लेकर तेहरान ले गई फोर्स.......

ईरान। भारतीय जहाज पर ईरान का हमला! स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने के दौरान कुक्रष्ट ने हमला कर जब्त किया, पिछले दिनों भी की थी ऐसी हरकत में एक बार फिर भारत आ रहे जहाज पर ईरान ने हमला किया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने के दौरान भारतीय जहाज पर गोलीबारी की। इसके बाद जहाज को जब्त कर अपने साथ ले गई। इन जहाजों की पहचान MSC Francesca और Epaminodes के रूप में की गई है। जहाजों के मालिकों से तुरंत संपर्क नहीं हो सका है। इनमें से

एक जहाज Epaminodes दुबई से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट आ रहा था। फिलहाल मामले में भारत सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि ये हमला डोनाल्ड ट्रंप के यूएस और ईरान सीजफायर बढ़ाने के बयान के बाद हुआ है। ट्रंप के ऐलान के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में तीन कार्गो शिप पर हमला हुआ है। गोलीबारी की घटना के बाद भी सभी सुरक्षित हैं। जहाज ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, ईरान की ओर से जब्त किया गया जहाज एपामिनोंडास गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जा रहा था। ये जहाज दुबई से अपनी यात्रा शुरू कर भारत की ओर आ रहा था कि तभी आईआरजीसी ने इस पर हमला कर अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय बंदरगाह की ओर जा रहे जहाज की इस जब्ती ने समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के नॉर्थ ईस्ट इलाके में गोलीबारी और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से अटैक किया गया है। लाइबेरिया का झंडा लगा एक कंटेनर जहाज के ब्रिज को नुकसान हुआ है। IRGC की एक गनबोट जहाज के करीब आ रही थी। इसके बाद ही जहाज पर हमला किया गया। फिलहाल जहाज में मौजूद सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं.

अब खेलों से चमकेगा बस्तर

सचिन तेंदुलकर ने कहा बस्तर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं

दंतेवाड़ा/ संवाददाता

दंतेवाड़ा के इंद्रावती किनारे बसे छिंदनार गांव ने उस पल इतिहास रच दिया, जब क्रिकेट जगत के महानायक सचिन तेंदुलकर अपने परिवार संग यहां पहुंचे। छिंदनार का खेल मैदान सचिन, सचिन. के नारों से गूंज उठा। इस दौरान बच्चों की आंखों में नए सपनों की चमक दिखाई दी। सचिन के साथ उनकी बेटी सारा तेंदुलकर, परिवार के सदस्य और मानदेशी फाउंडेशन की संस्थापक चेतना सिन्हा भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत खेल भावना से हुई, जहां सचिन ने बच्चों के साथ रस्साकशी में हिस्सा लिया। एक तरफ सचिन की टीम थी, दूसरी ओर बेटी सारा की टीम थी। मुकाबले में सारा की टीम ने जीत दर्ज की। इसके बाद मैदान में वो दृश्य दिखा, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। क्रिकेट के भगवान बच्चों संग वॉलीबॉल खेलते नजर आए। पूरे जोश के साथ खेल का आनंद लिया। इसके बाद सचिन ने मैदान का निरीक्षण किया और उन

लोगों को सम्मानित किया, जिन्होंने इस खेल परिसर को तैयार करने में योगदान दिया। दंतेवाड़ा जिले में अब तक 25 खेल मैदान तैयार हो चुके हैं, जबकि 25 और मैदानों की योजना पर काम जारी है। मंच से सचिन ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यह सफर 50 मैदानों पर नहीं रुकेगा बल्कि 100 से अधिक मैदानों तक पहुंचेगा। सचिन ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि यहां खिलाड़ी तो हैं, लेकिन मैदान नहीं तो उन्हें अपना बचपन याद आ गया।

उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी भी मैदान से शुरू हुई थी और वही मैदान बच्चों के भविष्य की दिशा बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मानदेशी फाउंडेशन और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन मिलकर यहां बच्चों को सिर्फ मैदान ही नहीं देंगे, बल्कि सही कोचिंग, सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षित शिक्षक भी देंगे, ताकि प्रतिभा सही दिशा पा सके। सचिन ने बस्तर के बच्चों को हीरे बताते हुए कहा कि यहां हजारों प्रतिभाएं छिपी हैं, जरूरत सिर्फ उन्हें तराशने की है। यही उम्र खेलने, सीखने, दोस्त बनाने और सपनों को आकार देने की है। अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उन्हें सबसे बड़ी सीख दी थी। क्रिकेट कितने साल चलेगा यह तय नहीं, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हें अच्छे इंसान के रूप में याद रखें। छिंदनार में सचिन का यह दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था। यह संदेश था कि अब बस्तर बंदूक नहीं, बल्ले और खेल के मैदानों से पहचाना जाएगा। सचिन अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा कर जगदलपुर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

पाकिस्तान तो फेल रहा

सही समय आने पर भारत निभाएगा भूमिका-राजनाथ

नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश की पर उसमे सफल नहीं हो पाया. दोनों देश अपनी-अपनी जिद पर अड़े हुए है. इन सबके बीच भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया है. रक्षामंत्री ने बर्लिन में एक बड़ा बयान दिया कि हर चीज का एक वक्त होता है, कल ऐसा समय भी आ सकता है कि जब भारत, ईरान और अमेरिका की जंग के बीच मध्यस्थता निभाए और इसमें सफलता भी हासिल करें. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ने दोनों पक्षों खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बात की थी और उनसे युद्ध खत्म करने की अपील भी की थी.ईरान और अमेरिका की जंग के बीच भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया है.

न.पं.नगरी की आपत्ति के बावजूद प्रभारी अधिकारी ने किया डायवर्सन आदेश पारित

कलेक्टर से संपूर्ण मामले की विस्तृत जांच करवाये जाने की मांग

धमतरी। राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नित नये कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इनके द्वारा शासकीय एवं आपत्तिजनक स्थलों के लिये लगाई गई आपत्ति का भी ध्यान न रखते हुए मनमाने आदेश करते है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ माह पूर्व नगरी सिहावा क्षेत्र में प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पद पर पदस्थापना के दौरान शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नियम विरूद्ध कई डायवर्सन आदेश जारी करने से दिया जा सकता है। एक प्रकरण में तो नगर पंचायत नगरी ने 20.2.26 को अनुविभागीय अधिकारी के पद के परिपालन में जारी पत्र में डायवर्सन पर आपत्ति दर्ज कराया गया है, बावजूद इसके उक्त आपत्ति को दरकिनार कर आनन-फानन में उक्त प्रकरण में आदेश जारी कर दिया गया। क्षेत्र में चल रही चर्चा के अनुसार प्रभारी अधिकारी के द्वारा जितने भी डायवर्सन केस या अन्य आदेश जारी किये गये हैं उसमें नियमों की अनदेखी की गई है। इसी तरह मामला चाहे राजाडेरा मगरलोड हो, चाहे भखारा क्षेत्र का हो, इसमें अधिकारियों ने अपने पद का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जो आदेश किया है, आज उसकी जांच फाईलों में कैद होकर बिना कार्यवाही के पड़ी हुई है। अब एक नया मामला सिहावा, नगरी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है जहां नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आपत्ति लगाये जाने के बाद भी एक डायवर्सन प्रकरण में एक व्यक्ति को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया गया है। उक्त व्यक्ति के संबंध में यह भी पता चला है कि इसने ऐसे अनेक डायवर्सन केस में आदेश कराये हैं। आदेश करने वाले अधिकारी मात्र 24 दिनों के लिये प्रभार में थे और उन्होंने इन 24 दिनों में अनेक डायवर्सन केस का निराकरण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है जिसे लेकर जागरूक नागरिकों के द्वारा लगातार इसके जांच की मांग कलेक्टर अबिनाश मिश्रा से की जा रही है। न्यायालय अनुविभागीय आधिकारी राजस्व के द्वारा विनय कुमार नारंग पिता सुरेश कुमार नारंग जाति सिंधी निवासी नगरी के द्वारा आवेदन पेश कर बताया गया था कि वे चुरियारा पहनं 23 तहसील नगरी जिला धमतरी में स्थित भूमि खसरा नंबर 1103/2 रकबा 0.0200 हे.(247.47 वर्ग मी.) भूमि को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ व्यपर्वन कराने बाबत आवेदन पत्र नक्शा खसरा, बी-1, ब्लू प्रिंट, शपथ पत्र संलग्न कर आवेदन उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें राजस्व निरीक्षक परिवर्तित नगरी से बिंदुवार जांच रिपोर्ट लिया जाये, नगर पंचायत, बिजली विभाग एवं पीडब्ल्यूडी से अनापत्ति मंगाई

जावे। नगर पंचायत ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि पर भू-व्यपवर्तन हेतु नगर पंचायत नगरी आपत्ति दर्ज करता है। अतएव अभिमत आपकी ओर प्रेषित है। यह आदेश 10.2.26 को किया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रकरण में संलग्न नहीं है। इसके बाद 24.2.26 को जो ऑर्डर शीट बनाई गई उसमें प्रकरण प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक परिवर्तित शाखा नगरी से बिंदुवार जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात अवलोकन किया गया और प्रकरण में आदेश पारित किया गया। इस प्रक्रिया में 10 फरवरी 2026 को जो आदेश जारी किया गया था उसके अनुसार राजस्व निरीक्षक के अलावा नगर पंचायत, बिजली विभाग एवं पीडब्ल्यूडी विभाग से अनापत्ति की प्रतीक्षा नहीं की गई और सीधा आदेश 24 फरवरी 2026 को कर दिया गया। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों में उपरोक्त तथ्यों के साथ साथ नगर पंचायत नगरी द्वारा दिनांक 20.2.26 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी जिला धमतरी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पंचायत नगरी ने पत्र क्रमांक 2672/नपं/राजस्व/25-26 प्रेषित करते हुए उक्त स्थल पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है। लेकिन प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आपत्ति का बिना निराकरण आदेश पारित कर दिया गया। खबर के मुताबिक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अवकाश में चले जाने के पश्चात पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रभार देते हुए मनोज मरकाम को यहां का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बनाया गया था जिन्होंने अपने 24 दिन के कार्यकाल में ऐसे अनेक प्रकरण में आदेश किया है जिनमें से एक प्रकरण 202602 130600005 वर्ष 25-26 में अनेक प्रकार की त्रुटियां होने के बाद भी आदेश किया गया है। नगर निवेश द्वारा उक्त भूमि विकास योजना में सम्मिलित नहीं होना भी बताया गया है जबकि उक्त भूमि नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रांतर्गत आता है। ऐसे में उक्त विभाग द्वारा लैंड यूज की जानकारी सहित एनओसी के बिना डायवर्सन करना नियमानुसार गलत प्रक्रिया है। यह एक प्रकरण में उपरोक्त त्रुटियां शामिल हैं। ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनमें प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा बिना एनओसी लिये डायवर्सन कराने वाले संबंधित व्यक्ति को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अवकाश में गये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के स्थान पर प्रभार संभाले उक्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के 24 दिन के कार्यकाल में अनेक डायवर्सन का मामला समूचे जिले में चर्चित है। अब जिलेवासियों की नजर जिले के संवेदनशील कलेक्टर अबिनाश मिश्रा पर टिकी हुई है कि वे इस प्रकार के डायवर्सन प्रकरण की जांच कब प्रारंभ करवाते हैं।उल्लेखनीय रहे कि राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जिस तरह स्वच्छ प्रशासन की छवि को कलंकित करने पर उतारू हैं, ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही में होने वाले विलंब से शिकायतकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इनका कहना है कि शासकीय भूमियों को विभिन्न निजी नामों पर दर्ज किये जाने से चारागाह, घास एवं शासकीय भूमि का निजीकरण हो रहा है। इन बेशकीमती भूमियों की सुरक्षा प्रशासन की होती है। लेकिन जब प्रशासन के कुछ अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करते हुए संबंधित भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाये तो शासकीय भूमि कैसे सुरक्षित रह सकेगी? मगरलोड विकासखंड के राजाडेरा में बेशकीमती भूमियों को शासकीय अभिलेखों में छेड़छाड़ कर उसे निजी व्यक्ति के नाम पर चढ़ाने वाले तहसीलदार पर अब तक कार्यवाही नहीं हुई वहीं भखारा क्षेत्र में भी ऐसा मामला सामने आया है जिसमें तहसीलदार, पटवारी ने भारी हेरफेर करते हुए निजी व्यक्ति को शासकीय भूमि आबंटित कर दी। ऐसे गंभीर मामलों में जितनी जल्दी कार्यवाही होगी, वैसे ही ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। अब जिलेवासियों की पूरी उम्मीदें संवेदनशील कलेक्टर मिश्रा पर टिकी हुई है जिनका जिले के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि नियम विरूद्ध कार्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अब उनके संज्ञान में उक्त पूरा प्रकरण आ चुका है। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि इस मामले की जांच बहुत जल्द होगी एवं नियम विरूद्ध डायवर्सन के पारित आदेश को निरस्त किया जायेगा और दोषियों पर उचित कार्यवाही होगी।

व्यापम की परीक्षाएं अब प्रात: 10 बजे से, दिशा निर्देश जारी

बलौदाबाजार। प्रदेश में बढ़ते तापमान को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिये समय प्रातः 10 से 12:15बजे तक निर्धारित किया गया है। आगामी 26 अप्रैल 2026 को व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में भी यही समय लागू होगा। जारी दिशा निर्देश अनुसार परीक्षार्थी, परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके।अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार 9.30 बजे बंद कर दिया जायेगा, इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देना होगा। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। फुटवियर के रूप में चप्पल पहनना होगा, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।परीक्षार्थी परीक्षा केन्द में केवल काले या नीले बॉल पांइट पेन का ही उपयोग करना है।

घरेलू और व्यवसायिक कचरा प्रबंधन की समस्याओं से जूझ रहा भंवरपुर

सड़क किनारे फेका गया कचरा गांव की सुंदरता पर लगा रहा ग्रहण

भंवरपुर। भंवरपुर की पहचान कभी 1980 के दशक में सड़क किनारे खुले में शौच की समस्या को लेकर होती थी। समय के साथ जागरूकता, सरकारी प्रयासों और विशेष रूप से स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव से इस गंभीर समस्या का समाधान हो गया। गांव ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई दिशा पकड़ी और खुले में शौच से मुक्ति पाई। हालांकि, बदलते परिवेश के साथ अब भंवरपुर एक नई चुनौती का सामना कर रहा है–कचरा प्रबंधन की समस्या। ज्ञात हो कि गांव में बढ़ती आबादी और व्यवसायिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाला कचरा अब एक

बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला ठोस कचरा और घरों से निकलने वाला मलबा बिना किसी निर्धारित व्यवस्था के सड़क किनारे या खाली स्थानों पर फेंका जा रहा है। इस अनियंत्रित कचरा निपटान के कारण न केवल गांव की सुंदरता प्रभावित हो रही है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ने लगे हैं। जगह-जगह जमा कचरा दुर्गंध फैलाता है और मच्छरों तथा अन्य हानिकारक जीवों के पनपने का कारण बनता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह भविष्य में गंभीर रूप ले सकती है। ग्रामवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि जिस तरह खुले में शौच की समस्या को जनजागरूकता और प्रशासनिक सहयोग से दूर किया गया, उसी तरह कचरा प्रबंधन के लिए भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें नियमित कचरा संग्रहण, कूड़ेदान की व्यवस्था, और लोगों को कचरा पृथक-करण के प्रति जागरूक करना शामिल है। स्थानीय प्रशासन से भी अपेक्षा की जा रही है कि वह इस दिशा में सक्रिय पहल करे और गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करे। यदि सामूहिक प्रयास किए जाएं, तो भंवरपुर एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में मिसाल बन सकता है।

दो सालों से पड़ा हुआ मलबा परेशानी का सबब

गौरतलब है कि ग्राम भंवरपुर में सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए मकान दुकान, छोटे-छोटे ठेले खोमचे आदि को प्रशासन द्वारा लगभग दो वर्ष पहले तोड़ा गया मगर अब तक मलबे को हटाया नहीं गया है। भंवरपुर के हृदय स्थल अटल चौक और आरा मिल के आसपास तथा जिला सहकारी बैंक के पास पड़ा हुआ मलबा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़े गए मकान दुकानों के ईंट, बोल्डर, लकड़ी, टीन, चद्दर आदि यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। इसे हटाने के लिए न तो अतिक्रमणकारी ध्यान दे रहे हैं, न ही प्रशासन और न ही ग्राम पंचायत।

धर्मांतरण पर सख्ती की मांग-हिन्दू जागरण मंच ने कलेक्टर, एसपी को सौंपा ज्ञापन

धमतरी। धमतरी जिले में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन को लेकर हिन्दू जागरण मंच ने पहल करते हुए जिलाधीश को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंच ने जिले में कथित रूप से प्रलोभन, दबाव एवं अन्य अनुचित माध्यमों से किए जा रहे धर्म परिवर्तन के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। हिन्दू जागरण मंच के जिला संयोजक पुरुषोत्तम निषाद के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को अवगत कराया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से समय.समय पर इस प्रकार की शिकायतें सामने आती रही हैं, जो सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़

सकता है। ज्ञापन में मांग की गई कि छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए अवैध धर्म परिवर्तन की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही बिना अनुमति संचालित प्रार्थना सभाओं एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने की भी आवश्यकता जताई गई। मंच ने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि इस दिशा में एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र विकसित किया जाए जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों को अपनी आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देना है। लेकिन किसी भी प्रकार के प्रलोभन, दबाव या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन करना कानूनन अपराध है। हिन्दू जागरण मंच ने जिलाधीश से अपेक्षा जताई कि प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाएगा और जिले में शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान मंच के पदाधिकारी दीपक सिंह ठाकुर, पुरूषोतम निषाद, डाकेश्वर साहू, प्रतीक सोनी, चित्रेश साहू, सत्यम सिन्हा, अभिषेक साहू, शिवांश पटवा, संजय साहू, संजीव चक्रधारी, दिव्या नेताम, भावना सिन्हा एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गुम हुए मोबाइल पुलिस प्रशासन तत्काल देने का काम करें : आशीष रात्रे

धमतरी। बसपा नेता आशीष रात्रे ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि चार महीने हो गए हैं, लेकिन पीड़ित लोगों को उनके मोबाइल उनके हाथ नहीं लगा है। उदाहरण के लिए सिटी कोतवाली क्षेत्र में जनवरी प्रथम सप्ताह में एक साथी का तीस हजार का मोबाइल गुम गया था। गुम मोबाइल की जानकारी सिटी कोतवाली में दी गई। तीन दिन बाद मोबाइल मिला जिसकी सूचना सिटी कोतवाली में दी गई। पीड़ित से मोबाइल जमा कर ली, दो चार दिन बाद मोबाइल ले जाना कहकर।

लेकिन बार.बार जाने के बाद भी मोबाइल नहीं दिया जा रहा है। बसपा नेता आशीष रात्रे ने कहा कि पीड़ित द्वारा आपबीती सुनाई गई तब पुलिस प्रशासन से पता चला कि सिटी कोतवाली से मोबाइल साइबर सेल में जमा कर रखें है। साइबर सेल से बात करने पर प्रभारी साइबर व्दारा बताया गया कि सभी थाना क्षेत्रों से इकट्ठा कर देंगे, एसपी का आदेश है कहकर बोला गया। सवाल यह कि मोबाइल में सभी जरूरी दस्तावेज रहते हैं। बसपा नेता आशीष रात्रे ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि बिना देर करे मोबाइल पीड़ित लोगों को वापस दिया जाये।

जीव जंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष आलोक सपरिवार शिवरीनारायण मठ में अक्ती तिहार के परंपरागत कलसी पूजा में शामिल हुआ

महासमुंद। छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष व कांग्रेस के प्रदेश संयुक्त महामंत्री आलोक चंद्राकर अक्षय तृतीया (अक्ति) के अवसर पर सपरिवार शिवरीनारायण पहुंचे। उन्होंने भगवान शिवरीनारायण के दरबार में पूरे परिवार के साथ दर्शन कर अक्ति तिहार में मठ में आयोजित परंपरागत कलसी पूजन कार्यक्रम में सपत्नीक शामिल हुए। उन्होंने भगवान शिवरीनारायण से छग की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। भगवान के दर्शन पश्चात मठ पहुंचे।

जहां उन्होंने भोजन प्रसादी ग्रहण किया। मठ में चंद्राकर और उनके माता का साल श्रीफल व भगवान शिवरीनारायण की तस्वीर भेंटकर सम्मान कर आशीष दिये। तत्पश्चात चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कराए गए विकास कार्यों अवलोकन की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने शिवरीनारायण की प्राचीन गौरवशाली परंपरा और छत्तीसगढ़ियों के भावना को ध्यान में रखकर विकास कार्य कराए थे। मंदिर दर्शन से पूर्व रेस्ट हाउस में कांग्रेसजनों व विभागीय अधिकारियों ने चंद्राकर का आत्मीय स्वागत किया। कांग्रेस नेता संदीप अग्रवाल और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य नारायण खंडेलिया के निवास जाकर उन्होंने मुलाकात की।

मुख्य सचिव विकासशील ने कलेक्टरों को विलेज एक्शन प्लान तैयार करने के दिए निर्देश

दल्लीराजहरा। प्रदेश के मुख्य सचिव विकासशील ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामों के निवासियों को जिला खनिज न्यास संस्थान निधि के राशि का समुचित लाभ सुनिश्चित कराने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विलेज एक्शन प्लान तैयार कर इसे ग्राम सभा में अनुमोदन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील संबंधित जिलों के कलेक्टरों एवं प्रभारी अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने अपने-अपने जिले के प्रभावित क्षेत्रों में जिला खनिज न्यास संस्थान निधि

के उपयोग हेतु प्रस्तावित कार्य योजना की भी विस्तृत समीक्षा की। इस मौके पर खनिज सचिव पी दयानंद, खनिज विभाग के संचालक रजत बंसल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने सभी जिला कलेक्टरों को विलेज एक्शन प्लान में प्रभावित क्षेत्रों के हितग्राहियों को शासन के विभिन्न 31 जन कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ सुनिश्चित कराने के अलावा इन ग्रामों में 14 बुनियादी आधारभूत अधोसंरचना से जुड़े कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करते हुए विलेज सैचुरेशन मॉडल पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासन के 10 विशेष प्राथमिकता वाले योजनाओं और 14 आधारभूत अधोसंरचना के कार्य जिला खनिज निधि की प्राथमिकता के आधार पर ही ग्रामवार वार्षिक कार्य योजना तैयार कर जिला के योजना तैयार की जाए तथा 15 मई तक इसे अंतिम रूप से वेबसाइट पर प्रकाशित कराएं और उसके अनुसार ही कार्य करें। मुख्य सचिव ने इसके आधार पर ही जिला खनिज न्यास संस्थान से कार्य की स्वीकृति एवं उनका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्षिक कार्य योजना में सूचीबद्ध कार्यों के लिए ही राशि स्वीकृत करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन एवं संशोधन बिल्कुल भी न की जाए। बैठक में कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत बालोद जिले को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों के संपादन हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्थापित बाजार को बनाएंगे आदर्श केंद्र: महापौर

किराए पर संचालित दुकानों पर होगी कार्रवाई, सभी को नोटिस जारी करने के निर्देश

दुर्ग। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत गौरवपथ स्थित महिला समृद्धि बाजार का आज महापौर अलका बाघमार द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रभारी शेखर चन्द्राकर एवं निगम बाजार विभाग अमला के समृद्धि बाजार परिसर का जायजा लिया तथा उपस्थित व्यापारियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। महापौर ने निरीक्षण के दौरान बाजार परिसर में व्याप्त स्वच्छता संबंधी खामियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बाजार में आने वाले ग्राहकों, विशेषकर महिलाओं के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान महापौर विभिन्न दुकानों में पहुंचीं और वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने यह भी जानकारी ली कि परिसर में कितनी दुकानों का आवंटन हुआ है तथा कितनी दुकानें किराए पर संचालित हो रही हैं। इस पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमों के विरुद्ध संचालित सभी दुकानों पर तत्काल कार्रवाई की जाए तथा संबंधित दुकान संचालकों को उसी दिन नोटिस जारी किया जाए। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार की स्थापना की गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को व्यवसायिक अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस उद्देश्य की पूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि बाजार की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएं, ताकि यह बाजार शहर की महिलाओं के लिए एक आदर्श व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो सके।

संक्षिप्त समाचार

वेदांता प्लांट हादसे में 24 मौतें, जांच और कार्रवाई पर उठे सवाल

रायपुर। वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 12 मजदूर अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस गंभीर घटना के बाद केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर जांच समितियों का गठन किया गया है। वहीं पुलिस ने प्लांट के चेयरमैन सहित 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। घटना को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने मामले की जांच के लिए अपनी 10 सदस्यीय टीम गठित की है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि दर्ज की गई एफआईआर केवल औपचारिकता है। उनका कहना है कि पुलिस ने जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया है, जबकि इस तरह की गंभीर घटना में सख्त और गैर-जमानती धाराएं लगनी चाहिए थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले को संवेदनशील बताकर जानकारी छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सांसद प्रतिनिधि ने जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे से पहले स्थानीय सांसद द्वारा तीन बार जिला कलेक्टर को प्लांट की सुरक्षा जांच और निरीक्षण के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका दावा है कि यदि समय रहते सुरक्षा उपायों पर ध्यान दिया गया होता, तो इतनी बड़ी दुर्घटना टाली जा सकती थी।

सीपीआई-माओवादी और उसके 6 फ्रंट संगठनों पर लगा प्रतिबंध

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल गतिविधियों में मदद करने वाले संगठनों पर एक्शन लेते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके 6 फ्रंट संगठनों पर लगे प्रतिबंध को एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इन संगठनों में दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच तथा आरपीसी अथवा जनताना सरकार शामिल है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत विधि विरूद्ध संगठन घोषित किया गया है। यह नई अधिसूचना 12 अप्रैल से प्रभावी होगी और अगले एक वर्ष की तक लागू रहेगी। राज्य शासन ने माना है कि इन संगठनों की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में बाधक बन रही हैं। जिसके चलते ये फैसला लिया गया है।

बाबा अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल, युवती गिरफ्तार

रायपुर। शहर के वैशाली नगर क्षेत्र में सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी ने माहौल गर्मा दिया। 21 वर्षीय युवती अनामिका उपाध्याय द्वारा इंस्टाग्राम पर डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक रील पोस्ट किए जाने के बाद अंबेडकर समर्थकों में तीव्र आक्रोश देखने को मिला। घटना की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी और अंबेडकरवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता भिलाई नगर थाने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की।

जनता की सुरक्षा हेतु प्रशासन सतर्क, शीतल जल केंद्र और कूलिंग शेल्टर शुरू

लू से बचाव के लिए जिला प्रशासन अलर्ट,व्यापक तैयारियों के निर्देश

रायपुर/ संवाददाता

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में संभावित लू (हीटवेव) की स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने एवं व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही जिले में लू चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा समन्वित कार्ययोजना लागू की जा रही है, जिससे जनहानि एवं स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को न्यूनतम किया जा सके। कलेक्टर डॉ. सिंह ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों एवं संवेदनशील आबादी की पहचान कर विशेष सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी अलर्ट प्रणाली के अनुसार रेड, ऑरेंज, येलो एवं सामान्य स्तर की चेतावनियों पर गंभीरता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, पार्क एवं सरकारी कार्यालयों में शीतल जल केंद्र (प्याऊ) स्थापित किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को निर्बाध रखने तथा नगर निगम के माध्यम से टैंकरों द्वारा जल वितरण की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही श्रमिकों एवं राहगीरों के लिए छायादार अस्थायी विश्राम केंद्र (कूलिंग शेल्टर) बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक प्रबंधन हेतु आवश्यक दवाएं, आई.वी. फ्लूड्स, ओआरएस पैकेट एवं कूलिंग ट्रीटमेंट सुविधाएं उपलब्ध रहें। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को हीटवेव प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा एम्बुलेंस सेवाओं को भी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग को गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं कुपोषित बच्चों की विशेष निगरानी करने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में ओआरएस एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही टीएचआर वितरण के दौरान महिलाओं को लू से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, बाजारों एवं प्रमुख स्थानों पर मिस्ट स्प्रे एवं वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था,

निर्माण स्थलों एवं ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों के लिए विशेष सतर्कता, तथा जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को लू से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, पर्याप्त पानी पिएं एवं स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर राज्य स्तरीय विविध कार्यक्रमों

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य शाखा रायपुर द्वारा 08 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के अवसर पर राज्य स्तरीय विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में रेडक्रॉस भवन, कलेक्टोरेट परिसर रायपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य शाखा के चेयरमैन श्री टोमन साहू ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्व रेडक्रॉस दिवस पर समूह नृत्य, प्रहसन एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेशभर के रेडक्रॉस वालंटियर्स भाग लेंगे। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बैठक में रेडक्रॉस की गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर जारी की गई। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) प्रशिक्षण, रक्तदान शिविरों का वृहद आयोजन तथा विभिन्न विशेष दिवसों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कार्ययोजना में जूनियर रेडक्रॉस एवं यूथ रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से विद्यार्थियों को मानवीय सेवा कार्यों से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है।

रायपुर नगर निगम से एक और फाइल गायब

रायपुर। रायपुर में नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित गार्डन से जुड़ी अहम फाइल गायब होने का मामला सामने आया है। पहले से ही फूड पार्क की शर्तों के उल्लंघन को लेकर विवादों में रहे इस गार्डन को लेकर अब प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कुछ दिन पहले जोन-10 से जुड़ी फाइल गायब होने की घटना सामने आई थी। अब मुख्यालय स्तर पर फाइल लापता होने से यह मामला और गंभीर हो गया है। अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, गार्डन के रखरखाव और सुविधाओं के लिए निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके तहत सीमित हिस्से में दुकानों और फूड स्टॉल की अनुमति दी गई थी, लेकिन आरोप है कि निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग किया गया। निगम के नियमों के मुताबिक, उद्यान के कुल क्षेत्रफल के केवल 5 प्रतिशत हिस्से में ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। साथ ही सुरक्षा, साफ-सफाई और सीसीटीवी व्यवस्था सुनिश्चित करना भी एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद मौके पर इन व्यवस्थाओं में कमी और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आती रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि गड़बड़ियों को छिपाने के लिए दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई हो सकती है। महापौर मोनल चौबे का कहना है कि गार्डन से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की अकर्मण्यता से छत्तीसगढ़ में पेयजल संकट,हर घर नल का दावा झूठा

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी शुरू होते ही उत्पन्न पेयजल संकट के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि जल जीवन मिशन (हुहुरू) के तहत घर-घर नल पहुंचाने का कार्य पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में हुआ था लेकिन सरकार बदलते ही पेयजल परियोजनाओं पर ग्रहण लग गया, ठेकेदारों का भुगतान दुर्भावना पूर्वक रोके जाने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन (क्काश्च विभाग की उदासीनता) नहीं हो रहा है जिसके चलते ही रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जशपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर और सूरजपुर सहित पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति निर्मित हो गई है। राजधानी रायपुर के 70 में से 35 वार्ड जल प्रभावित हैं, शहर के लगभग आधे हिस्से में पानी की भारी किल्लत है, मरम्मत के अभाव में पाइपलाइन खराब होने के कारण समस्या और बढ़ गई है। टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई है, ट्रिपल इंजन सरकार जनता के लिए ट्रबल इंजन साबित हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि सरकार के कुप्रबंधन के कारण जल स्तर में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण ही गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैध रूप से भूजल का अत्यधिक दोहन, उद्योगों को प्राथमिकता देने की वजह से बांध और ऐनीकट तेजी से खाली हो रहे हैं। अप्रैल के महीने में ही कई इलाकों में 300-400 फीट नीचे भी पानी नहीं है, जिससे ग्रामीण ढोढ़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हैंडपंप और बोरवेल जवाब दे रहे हैं, पुराने बोरवेल का उचित रखरखाव तक नहीं कर पा रही है सरकार। जल जीवन के तहत भी जहां 80 से 90 प्रतिशत काम हो चके हैं वहां पर भी सरकार ने काम रोक दिया है जिसमें जनता को लाभ नही मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि इस साल पर्याप्त वर्षा और जलाशय में पुरी क्षमता के स्टोर के बावजूद सरकार की कॉर्पोरेट परस्त नीतियों की वजह से डैम का पानी तेजी से खाली हो रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने बदली मन्नू-बिमला राठौर की जिंदगी

- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीणों को मिल रहा सुरक्षित आवास
- कच्चे घर से पक्के मकान तक का सफर बना प्रेरणादायक

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में साय सरकार के संवेदनशील नेतृत्व और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना तेजी से साकार हो रहा है। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण जनपद पंचायत गौरेला के ग्राम पंचायत गोरखपुर में देखने को मिला, जहां श्री मन्नू राठौर और उनकी पत्नी श्रीमती बिमला राठौर ने योजना का लाभ लेकर अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। कभी कच्चे और जर्जर मकान में जीवन यापन करने वाला यह परिवार हर मौसम में कठिनाइयों का सामना करता था। बरसात में टपकती छत, गर्मी और सर्दी में असुरक्षित वातावरण ने उनके जीवन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना रखा था। सीमित आय के कारण पक्का घर बनाना उनके लिए एक दूर का सपना था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति मिली। यह आर्थिक सहायता उनके जीवन में नई उम्मीद बनकर आई। योजना से प्राप्त राशि और अपनी मेहनत के बल पर मन्नू राठौर ने धीरे-धीरे अपने सपनों का पक्का घर तैयार कर लिया। आज उनका परिवार एक सुरक्षित, स्वच्छ और मजबूत मकान में निवास कर रहा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिला है, वहीं पूरे परिवार के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। श्रीमती बिमला राठौर बताती हैं कि अब उन्हें बारिश या तूफान की कोई चिंता नहीं रहती और वे अपने घर में गर्व और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी है। साय सरकार की प्रतिबद्धता के चलते ही आज हजारों जरूरतमंद परिवारों को न केवल पक्का आवास मिल रहा है।

भाजपा की रैली में आंगनबाड़ी और मितानिन कार्यकर्ता-धनंजय ठाकुर

- महिला शिक्षिको को दबावपूर्वक बुलाया गया क्या यही नारी वंदन है?

रायपुर। संवाददाता

भाजपा की राजनीतिक रैली में आंगनबाड़ी, मितानिन कार्यकर्ताओं, महिला शिक्षकों को दबावपूर्वक बुलाने का गम्भीर आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की राजनीतिक रैली के लिए सरकारी तंत्रों का भारी दुरुपयोग किया गया। उच्च अधिकारियों ने दबावपूर्वक आंगनबाड़ी, मितानिन कार्यकर्ताओं एवं महिला शिक्षकों को मौखिक आदेश देकर रैली में शामिल होने दबाव डाला। आंगनबाड़ी, मितानिन को महिलाओं की भीड़ लाने एवं महिला शिक्षकों को हेलमेट लगाकर दुपहिया लेकर रैली में शामिल होने कहा गया, क्या यही भाजपा की नारी वंदन है? शासकीय महिला कर्मचारियों को नौकरी का खतरा ट्रांसफर का डर दिखाया गया? परिवहन विभाग गाड़ियों की व्यवस्था की, सरकारी तंत्र एवं भ्रष्टाचार के पैसे से रैली की व्यवस्था की गई। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि असल में भाजपा के भीतर ही महिला आरक्षण बिल संशोधन विधेयक के खिलाफ आवाज उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती तो खुलकर विरोध कर रही है। वसुंधरा राजे ने तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर उनके मौन रहने पर सवाल उठाये एवं परिसीमन बिल को गलत बताया है। वही उमा भारती ने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग कर कर कांग्रेस की मांग का एक प्रकार से समर्थन किया है।

सीटों के परिसीमन का भाजपा षडयंत्र विफल

रायपुर। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर भाजपा परिसीमन बलि पास कराना चाह रही थी। जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि भाजपा की यह रणनीति अब जनता के सामने आ चुकी है। जब महिला आरक्षण पहले ही 2023 में पारित किया जा चुका है, तो चार राज्यों में चुनाव के समय संसद का विशेष सत्र बुलाकर पास कराने के पीछे की मंशा क्या थी। कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में हमेशा रही। पार्टी ने परिसीमन बिल का विरोध किया। अब भाजपा के इस षडयंत्र का कांग्रेस पर्दाफास करेगी। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पु बंजारे, दीप्ति दुबे, वार्ड अध्यक्ष अर्जुमन डेबर सहित कई कांग्रेस नेताओं ने अपने पक्ष रखे। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के परिसीमन बिल पर अन्य राज्यों को आपत्ति थी, भाजपा महिला आरक्षण को सामने रख कर परिसीमन चाहती थी। भाजपा 2011 के जनगणना पर परिसीमन करना चाहती है। जब 2026-27 वहीं तो जनगणना के सरकार जाति जनगणना की भी बात कर चुकी है आधार पर परिसीमन क्यों नहीं कराया जा रहा? महिला आरक्षण बिल को यदि करना है तो परिसीमन का इंतजार किये बिना वर्तमान सदस्य संख्या का आधा क्यों नहीं देना चाहती सरकार? सरकार 2023 महिना नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना क्यों नहीं चाहती। जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2021 जो कानून बन चुका है 2036 से मूर्त रूप लेगा संशोधन से तुरंत लागू हो जाता।

अंबिकापुर में 'श्री अग्रोहा पैलेस' का भूमिपूजन

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दिया समाज को नई दिशा का संदेश

- भवन नहीं, जीवंत समाज बनाएं अग्रोहा पैलेस भूमिपूजन पर बृजमोहन अग्रवाल का आह्वान
- नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने की जरूरत अग्रोहा पैलेस भूमिपूजन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल बोले

रायपुर/ संवाददाता

रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को अंबिकापुर में अग्रवाल समाज के 'श्री अग्रोहा पैलेस' का भूमिपूजन किया। 150 अत्याधुनिक कमरों, विशाल हॉल और सर्वसुविधायुक्त लॉन से बनने वाला यह भव्य भवन छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य भारत में अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम भगवान अग्रसेन जी महाराज के वंशज हैं और अग्र समाज का इतिहास हमेशा से सेवा और समर्पण का रहा है। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने तीर्थ स्थलों पर भवन, बावड़ियां और अन्न क्षेत्र बनाकर समाज सेवा की अनूठी परंपरा कायम की है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 'श्री अग्रोहा पैलेस' का निर्माण एक सराहनीय पहल है। सांसद श्री अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे समाज की परंपरा आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। जहां-जहां पुराने तीर्थ स्थल हैं, वहां अगर भवन बने हैं, बावड़ियां बनी हैं या अन्न क्षेत्र बने हैं, तो उसमें अग्रवाल समाज का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज हमारी नई पीढ़ी इस दिशा में उतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही है, यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम आज भी अपने पूर्वजों के कार्यों का गौरव गान करते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम स्वयं भी वैसा ही योगदान दें। समाज में संस्कारों की कमी आ रही है, और यह हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, घर तब बनता

है जब उसमें बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। उसी तरह यह भवन भी तभी सार्थक होगा, जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी होगी। सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि जब तक समाज का कमजोर व्यक्ति इस भवन से नहीं जुड़ेगा, तब तक यह केवल एक बिल्डिंग बनकर रह जाएगा। जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल करें, ताकि उन्हें लगे कि यह उनके लिए बना है और उनके काम आएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज को केवल भव्य भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था जैसे कार्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने समाज के गरीब और किराए के घर में रहने वाले परिवारों को अपना घर दे दें, तो इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। सांसद श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि भवन बनाना एक बात है, लेकिन उसे जागृत और जीवंत बनाना अलग बात है। जब यह भवन समाज के हर वर्ग के उपयोग में आएगा, तभी इसकी वास्तविक सार्थकता होगी। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मंदिर में हम भगवान की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन यदि हमने एक बच्चे को शिक्षित कर दिया या किसी गरीब का इलाज करा दिया, तो उससे बड़ा भगवान कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'श्री अग्रोहा पैलेस' समाज को जोड़ने, संस्कारों को सशक्त करने और सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, अग्रवाल सभा अंबिकापुर अध्यक्ष श्री संजय मित्तल, श्री अजय अग्रवाल, बाबूलाल गोयल, श्री योगेश अग्रवाल, संजय, विनोद, कृष्ण कुमार, श्री मनोज जैन समेत बड़ी संख्या में समाज के गणमान्यजन की गरिमामयी उपस्थिति रही।

संपादकीय

होर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी से नई जटिलता खड़ी होगी

होर्मुज जलमार्ग के पूरी तरह बंद होने के बाद भारत सहित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में संकट गहरा सकता है। इसके अलावा, अगर रूस और चीन भी इस संकट की जद में आते हैं, तो एक नई जटिलता खड़ी होगी।करीब डेढ़ महीने बाद बहुत मुश्किल से पहले युद्धविराम और फिर शांति की राह तैयार करने के मकसद से ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता की गुंजाइश बनी थी। अतीत से लेकर वर्तमान तक दोनों देशों के बीच जैसे संबंध रहे हैं, उसमें अचानक ही सब कुछ पटरी पर आ जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन कम से कम युद्ध रुकने और दीर्घकालिक हल निकालने के लिए संवाद कायम रखने की गुंजाइश जरूर बनी थी।अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्ता के विफल होने के बाद बातचीत के जरिए शांति की संभावना तैयार करने के बजाय एक ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टकराव की भाषा का सहारा लेना शुरू कर दिया है, तो दूसरी ओर ईरान ने भी अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब देने की बात कही है।इस बीच युद्धविराम लागू होने के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर अपने हमले जारी रखे। ऐसी स्थिति में यह समझना मुश्किल नहीं है कि शांति प्रयासों के लिए होने वाली कवायदों और स्थायी हल निकालने की कोशिशों के सामने कैसी चुनौती खड़ी हो सकती है।गौरतलब है कि ईरान के साथ वार्ता के विफल होने के बाद ट्रंप ने बेहद तल्ख जुबान में कहा कि ईरान होर्मुज जलमार्ग को खोल दे, नहीं तो अमेरिका समूचे इलाके की नाकेबंदी कर देगा। इसके जवाब में ईरान की ओर से कहा गया कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में सुरक्षा या तो सभी के लिए होगी या किसी के लिए भी नहीं।ईरान का कहना है कि अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो इस क्षेत्र का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। सवाल है कि अगर दोनों ही अपनी धमकियों पर अड़े रहते हैं, तो इसका हासिल क्या होगा। युद्ध को खत्म करने के लिए जहां नए रास्तों की तलाश की जानी चाहिए थी, वहीं पहली बैठक में मिली नाकामी के बाद दोनों ओर से हमलावर रुख का प्रदर्शन किया जा रहा है।एक आशंका यह भी पैदा हो रही है कि एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने को लेकर अगर दोनों पक्षों की भाषा में नरमी नहीं आई, तो इसका असर युद्धविराम पर भी पड़ सकता है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि अगर होर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी को लेकर अमेरिका की धमकी वास्तव में अमल में आती है, तो आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट की वजह से हालात कैसे हो सकते हैं।ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया हुआ है, लेकिन उसने कुछ देशों को वहां से गुजरने की इजाजत दी हुई है। कुछ अन्य देशों को भी छूट देने की बात चल रही थी। अब जहां कोशिश इस बात की होनी चाहिए थी कि होर्मुज जलमार्ग को खोलने सहित अन्य मुद्दों पर टकराव को खत्म करके स्थायी शांति का रास्ता तैयार किया जाए, वहां नए सिरे से टकराव का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है।अमेरिका की ओर से युद्ध में अपना पलड़ा भारी करने की जिद की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, जिसका खमियाजा वैसे देश ज्यादा उठाएंगे, जो तेल और गैस के लिए फिलहाल काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि दुनिया भर के देशों में तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलमार्ग से होकर ही गुजरता है। इसके पूरी तरह बंद होने के बाद भारत सहित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में संकट गहरा सकता है। इसके अलावा, अगर रूस और चीन भी इस संकट की जद में आते हैं, तो एक नई जटिलता खड़ी होगी।

सबरीमाल पर धर्म और कानून में महासंग्राम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासत में आएगा तूफान?

धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक शांति प्रिय धर्म के बारे में सुनवाई और दिशानिर्देश, जबकि दूसरे-तीसरे कट्टर धर्म के बारे में अपेक्षित सुनवाई पर टालमटोल ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि प्रबुद्ध हिंदुओं के संज्ञान में सारी बातें आईने की तरह चमक रही हैं और कॉन्वेंट एजुकेटेड लोगों से ज्यादा अपेक्षा भी किसी को नहीं है। लिहाजा, केंद्र सरकार और न्यायमूर्ति के स्टैंड अपनी अपनी जगह पर सही हैं, इसलिए भारतीय जनता के व्यापक हित में फैसला आना चाहिए, न कि पीक एंड चूज! जैसा कि विभिन्न विवादास्पद मामलों में प्रतीत होता है। सरकार और न्यायालय से जुड़े लोगों से बहुमत का पक्ष लेने की अपेक्षा नहीं कि जाती है, बल्कि बिटवीन द लाइंस की तरह ऐसा निर्णय आना चाहिए, जिसपर तर्क-वितर्क की कोई गुंजाइश ही न बने।

(कमलेश पांडे)

सबरीमाला प्रकरण के बहाने यह लेख भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव का विश्लेषण करता है, जिसमें धार्मिक प्रथाओं पर न्यायिक हस्तक्षेप और 'चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता' पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेख मांग करता है कि संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्ट कानून या निष्पक्ष न्यायिक निर्णय हो, अन्यथा लोकतांत्रिक बहस व्यवस्था पर हावी हो जाएगी।

सबरीमाला प्रकरण के बहाने भारतीय लोकतंत्र में, संसद और संविधान के

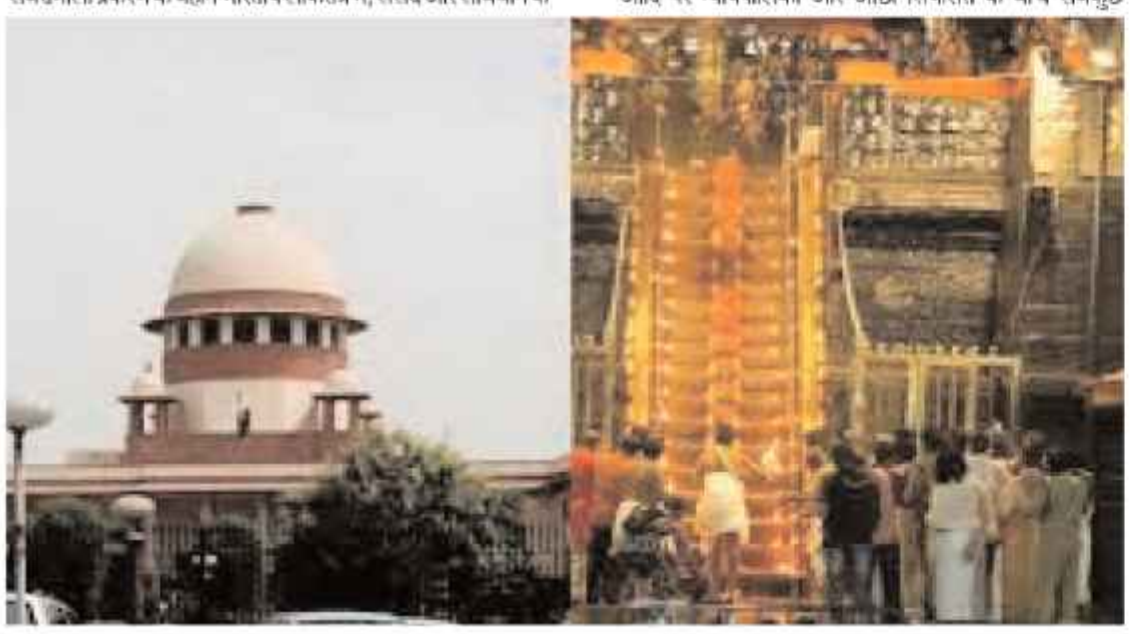

दायरे में, सियासत और न्यायपालिका के मठाधीशों के नजरिए में, क्या सही है और क्या गलत? क्या जिम्मेदारी है और क्या नहीं?, यह बहस का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पष्ट कार्रवाई नजर आनी चाहिए। या तो सियासतदान, संसद और विधानमंडलों में कानून स्पष्ट बनाएं या फिर सुलगते सवालों पर न्यायपालिका के न्यायाधीशगण स्वतः संज्ञान लेकर निष्पक्ष न्यायदेश देने की पहल करें, क्योंकि आम जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए।

हालांकि, व्यवहारिक कसौटी पर ये बातें पूरी तरह से खरी नहीं उतरती हैं। इसलिए अपेक्षा है कि धर्म सम्मत न्याय दीजिए, अन्यथा लोकतांत्रिक तर्क-वितर्क भारी पड़ेगा!

धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक शांति प्रिय धर्म के बारे में सुनवाई और दिशानिर्देश, जबकि दूसरे-तीसरे कट्टर धर्म के बारे में अपेक्षित सुनवाई पर टालमटोल ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि प्रबुद्ध हिंदुओं के संज्ञान में सारी बातें आईने की तरह चमक रही हैं और कॉन्वेंट एजुकेटेड लोगों से ज्यादा अपेक्षा भी किसी को नहीं है।

लिहाजा, केंद्र सरकार और न्यायमूर्ति के स्टैंड अपनी अपनी जगह पर सही हैं, इसलिए भारतीय जनता के व्यापक हित में फैसला आना चाहिए, न कि पीक एंड चूज ! जैसा कि विभिन्न विवादास्पद मामलों में प्रतीत होता है। सरकार और न्यायालय से जुड़े लोगों से बहुमत का पक्ष लेने की अपेक्षा नहीं कि जाती है, बल्कि बिटवीन द लाइंस की तरह ऐसा निर्णय आना चाहिए, जिसपर तर्क-वितर्क की कोई गुंजाइश ही न बने।

बीच बहस में पड़ने का दूसरा अदृश्य पहलू यह है कि आम तौर पर किसी न्यायाधीश या नौकरशाह की बुद्धि आम बहुमतधारी नेताओं की बुद्धि से औसत रूप में अच्छी समझी जाती है! फिर भी जब राजनीतिक अतिरेक पर, धार्मिक चुनौतीपन पर, व्यक्तिगत विभेद आदि पर न्यायपालिका और ओछी सियासत के बीच सबकुछ गड्डमड्ड दिखाई देने लगता है तो न्यायिक विवेक और विधायी विवेक के ऊपर सवाल उठना लाजिमी है। यही पर जनमत को प्रभावित करने वाले संपादकीय विवेक का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है! पर दुर्भाग्य की बात है कि इसे भी खुल्लमखुल्ला बाजार बनने को अभिशप्त बना दिया गया है।

सुलगता सवाल है कि आखिर विधायिका और न्यायपालिका देश के सुलगते हुए सवालों का हल बीते सात-आठ दशकों में भी क्यों नहीं ढूंढ पाई हैं? वहीं सामाजिक न्याय और साम्प्रदायिक सोच से जुड़े मसलों पर कड़वा सच कहने का हौसला नहीं प्रदर्शित कर पाई। इससे बहुमत का नँगानाच बढ़ा और मानवीयता नकार दी गई। विधिवत पक्षपात दिखता रहा, लेकिन न्यायविदों की खामोशी पीड़ितों की सिसकन पर भारी पड़ी। यह कोई उलाहना नहीं, बल्कि आपकी अंतरात्मा को झकझोरने की एक पहल है। आखिर कई बार न्यायपालिका/कार्यपालिका भीड़तंत्र के समक्ष घुटने टेकती हुई प्रतीत क्यों होती हैं? यक्ष प्रश्न है।

खैर, जब जब ऐसा हुआ, उन्हें संपादकीय विवेक सम्मत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके मुद्दे जस के तस बने हुए हैं और व्यवस्था पूंजीवादी सोच के प्रति नतमस्तक नजर आती है, क्योंकि दीपावली उपहार तो किसान-मजदूर-कारीगर कभी दे नहीं सकते। सबसे बड़ा सवाल यह कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन पर यानी संविधान की नौवीं अनुसूची पर न्यायिक चुप्पी आजतक प्रबुद्ध लोगों को खल रही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है तो ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सके, जैसा कि प्रथम संवैधानिक संशोधन के बाद प्रचलन में आया। यह तो महज एक बानगी है, अन्यथा कार्यपालिका की हरकतों पर न्यायपालिका की लाचारी दिखाती है कि लोकतंत्र आना अभी शेष है!

दरअसल, सबरीमला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गत 8 अप्रैल, दिन बुधवार को एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि उसके पास यह तय करने का अधिकार है कि किसी धर्म में कौन-सी प्रथा अंधविश्वास है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, अगर विधायिका चुप रहे तो न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती? बता दें कि कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र सरकार के उस तर्क के जवाब में आई, जिसमें कहा गया था कि अदालत यह तय नहीं कर सकती कि कोई धार्मिक प्रथा अंधविश्वास है या नहीं।

मसलन, केंद्र का कहना था कि जज कानून के विशेषज्ञ होते हैं, धर्म के नहीं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संवैधानिक नैतिकता और ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में संवैधानिक नैतिकता को आधार नहीं बनाया जा सकता। मेहता ने कहा कि यह न्यायिक समीक्षा का स्वतंत्र आधार नहीं हो सकता।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने पूछा, अदालत कैसे तय कर सकती है कि कोई प्रथा अंधविश्वास है। भले कोई प्रथा अंधविश्वासी हो, उसे ऐसा घोषित करना अदालत का काम नहीं है। कानून बनाना विधायिका का अधिकार है। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, कोर्ट के पास यह कहने का अधिकार है कि कोई प्रथा अंधविश्वास है या नहीं।

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा- समाज में नैतिकता समय के साथ बदलती है। किसी प्रथा को अंधविश्वासी मानने का अधिकार कोर्ट के पास है? सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि अगर विधायिका चुप रहे तो क्या न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, विधायिका चुप रहे तो? मेहता ने कहा, भारत जैसे विविध समाज में एक समुदाय की धार्मिक प्रथा दूसरे के लिए अंधविश्वास हो सकती है। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने पूछा, कोई समुदाय जादूटोना को प्रथा बताए, तो उसे अंधविश्वास नहीं माना जाएगा? अगर अनुच्छेद 32 के तहत मामला कोर्ट में आए और विधायिका चुप रहे तो?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो लोग भगवान अयप्पा के भक्त नहीं है, क्या वे मंदिर की परंपराओं को चुनौती दे सकते है? सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बताया कि मूल याचिका इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने दायर की थी। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया कि क्या गैर-भक्त को ऐसा अधिकार है?

दरअसल, सबरीमला केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ कर रही है। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश से जुड़े, सबरीमला विवाद मामलों पर सुनवाई चल रही है। इसी पर केंद्र ने कहा- धर्म में अंधविश्वास है या नहीं, यह तय करना अदालत का काम नहीं है। जब भक्त नहीं तो चुनौती कैसे दे सकते है? यहां पर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है, लेकिन मामले का सकारात्मक हल निकले, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

डिजिटल युग में हिंदी- चुनौतियाँ और संभावनाएँ

(स्निग्धा)

मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर सिमटती दुनिया में शब्दों की गहराई कहीं धीरे-धीरे धुंधली होती प्रतीत होती है। डिजिटल युग ने ज्ञान को हमारी उँगलियों तक पहुँचा दिया है; सूचना का विस्तार अभूतपूर्व है। परंतु भाषा से हमारा आत्मीय रिश्ता पहले जैसा सशक्त नहीं रहा। तकनीक आज जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है–शिक्षा, संवाद, शोध और मनोरंजन–सब कुछ डिजिटल माध्यमों से जुड़ गया है। ऐसे में शिक्षण पद्धति में परिवर्तन स्वाभाविक है, किंतु इस परिवर्तन के बीच हिंदी भाषा का शिक्षण नई परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर रहा है।

एक हिंदी शिक्षिका के रूप में प्रतिदिन यह अनुभव होता है कि बच्चों के विचारों में कमी नहीं है। वे जिज्ञासु हैं, कल्पनाशील हैं, संवेदनशील भी हैं। परंतु जब उन विचारों को शब्दों में ढालने का समय आता है, तो वे ठिठक जाते हैं। हाल ही में, कक्षा में विद्यार्थियों से उनके मनपसंद विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखने को कहा। सभी के पास भाव थे, अनुभव थे, पर शब्द नहीं। कई विद्यार्थियों ने सहज भाव से कहा–सोच तो है, पर लिखने के लिए शब्द नहीं मिलते। उस क्षण यह स्पष्ट हुआ कि समस्या प्रतिभा की नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की है।

कम हो रही लंबे वाक्य लिखने की प्रवृत्ति

डिजिटल माध्यमों ने संवाद को त्वरित और संक्षिप्त बना दिया है। चैट भाषा, इमोजी और मिश्रित भाषायी प्रयोग (हिंग्लिश) का प्रभाव बच्चों की हिंदी शब्दावली को सीमित कर रहा है। लंबे वाक्य लिखने की प्रवृत्ति कम हो रही है। शुद्ध वर्तनी और व्याकरणिक सावधानी पर ध्यान घटता जा रहा है। 'है' और 'हैं', 'क्योंकि' और 'क्युकी', 'वहाँ' और 'वहा' जैसे सरल शब्दों में भी भ्रम देखने को मिलता है। कई बार बच्चे अपनी त्रुटियाँ पहचानने में भी असमर्थ होते हैं। जब भाषा की बुनियाद कमजोर होती है, तो आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है।

वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश के अनेक प्रतिष्ठित विद्यालय, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं, अपनी शिक्षण पद्धति में मुख्य रूप से अंग्रेजी माध्यम का उपयोग करते हैं। यद्यपि यह बोर्ड हिंदी माध्यम के विद्यालयों को भी पूरी मान्यता प्रदान करता है, फिर भी व्यवहार में अधिकांश विद्यार्थी अन्य विषयों का अध्ययन अंग्रेजी में करते हैं। यह स्वाभाविक है कि विद्यार्थी जिस भाषा में विज्ञान या गणित जैसे विषय पढ़ते हैं, वे उसी में अधिक सहज हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, हिंदी उनके लिए अभिव्यक्ति का माध्यम कम और केवल एक 'विषय' अधिक बनकर रह जाती है।

अंग्रेजी का महत्व बढ़ा

?अभिभावकों की प्राथमिकताओं में भी अंग्रेजी का महत्व बढ़ा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को वैश्विक अवसरों के लिए सक्षम बनाना है। इस प्रयास में अनजाने में घर और विद्यालय दोनों स्थानों पर हिंदी के सक्रिय प्रयोग और पठन के अवसर सीमित हो जाते हैं।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समस्या किसी अन्य भाषा के अस्तित्व से नहीं है। बहुभाषिकता हमारे देश की शक्ति है। अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। किंतु जिस भाषा में बच्चा अपने परिवेश को समझता है और भावनात्मक रूप से जुड़ता है, उसमें दक्षता उसके चिंतन को गहराई प्रदान करती है। यही कारण है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में शिक्षण को महत्व देती है, क्योंकि भाषा ही विचारों की आधारशिला है।

संतुलन में है समाधान

समाधान निराशा में नहीं, संतुलन में है। यदि हिंदी को केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित न रखकर जीवन से जोड़ा जाए, तो वह पुनः बच्चों के लिए सहज और रोचक बन सकती है। कहानी-कथन, समूह-चर्चा, भूमिका-अभिनय, वाद-विवाद, रचनात्मक लेखन और काव्य-पाठ जैसी गतिविधियाँ विद्यार्थियों के शब्द-भंडार और आत्मविश्वास को सुदृढ़ कर सकती हैं। विद्यालयों में नियमित पठन-अभियान, 'दिन का शब्द' जैसी पहलें और पुस्तकालय संस्कृति का सशक्तिकरण भी महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

डिजिटल साधनों को विरोधी नहीं, सहयोगी बनाया जा सकता है। यदि तकनीक का प्रयोग हिंदी ब्लॉग, ई-पत्रिका, ऑडियो-पुस्तक और रचनात्मक लेखन मंचों के माध्यम से किया जाए, तो बच्चे उसी डिजिटल संसार में हिंदी से जुड़ सकते हैं, जहाँ वे पहले से सक्रिय हैं।

वास्तव में भाषा केवल एक विषय नहीं, बल्कि संस्कृति, संवेदना और चिंतन की धुरी है। जब शब्द सशक्त होते हैं, तभी विचार स्पष्ट और प्रभावी बनते हैं। हिंदी को जीवंत बनाए रखना केवल शिक्षक का दायित्व नहीं, बल्कि अभिभावकों, विद्यालयों और समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। यदि हम बच्चों को शब्दों का समृद्ध संसार दे पाएँ, तो वे अपने विचारों से भविष्य को और अधिक उज्ज्वल बना सकेंगे।(स्निग्धा चेन्नई स्थित विद्यालय में हिंदी शिक्षिका हैं। लेख में प्रस्तुत विचार लेखक के निजी विचार हैं।

नीतीश कुमार होने के मायने

ऐसे समय में नीतीश कुमार आए। न घोषणाओं के शोर के साथ, न सत्ता के अहंकार के साथ, बल्कि एक शांत संकल्प के साथ। जैसे कोई बड़ा भाई टूटते घर की दीवारों को चुपचाप सहारा देता है। उन्होंने सबसे पहले उस भय को तोड़ा, जिसने बिहार की आत्मा को जकड़ रखा था। तेज़ ट्रायल की व्यवस्था, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और प्रशासनिक जवाबदेही, इन सबने मिलकर एक नया संदेश दिया कि अब कानून केवल किताबों में नहीं, जमीन पर भी दिखेगा। आंकड़े बताते हैं कि उनके शुरुआती कार्यकाल में ही लगभग 1.5 लाख से अधिक आपराधिक मामलों का त्वरित निपटारा हुआ और 50,000 से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई।

(प्रणय विक्रम सिंह)

आज बिहार की राजनीति के आंगन में एक अजीब सी नमी उतर आई है। जैसे किसी घर से बेटी विदा हो रही हो। आंगन वही है, दीवारें वही हैं, दरवाज़ा भी खुला है,पर भीतर एक सूनापन धीरे-धीरे फैलता जा रहा है। मां की आंखें भरी हैं, भाई की आवाज़ अटक गई है और घर का हर कोना मानो स्मृतियों में सिमट गया है।

मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार का इस्तीफा भी कुछ ऐसा ही है। यह सत्ता का परिवर्तन नहीं, एक संवेदना का संधि-विराम है। एक ऐसे युग का अवसान, जिसने बिहार को अंधकार से आलोक, अव्यवस्था से अनुशासन और भय से विश्वास तक पहुंचाया।

एक समय था जब बिहार का नाम सुनते ही मन में भय की परछाइयां उतर आती थीं। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में यह राज्य अपहरण, अपराध और अराजकता की त्रासदी से जूझ रहा था। अपहरण उद्योग एक कड़वी सच्चाई बन चुका था, कानून-व्यवस्था चरमराई हुई थी, और जातीय संघर्षों की आग गांव-गांव तक फैली हुई थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासन की उपस्थिति वैसी ही थी, जैसे किसी सूखे खेत में बादलों की परछाई दिखती तो है, पर बरसती नहीं।

ऐसे समय में नीतीश कुमार आए। न घोषणाओं के शोर के साथ, न सत्ता के अहंकार के साथ, बल्कि एक शांत संकल्प के साथ। जैसे कोई बड़ा भाई टूटते घर की दीवारों को चुपचाप सहारा देता है। उन्होंने सबसे पहले उस भय को तोड़ा, जिसने बिहार की आत्मा को जकड़ रखा था। तेज़ ट्रायल की व्यवस्था, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और प्रशासनिक जवाबदेही, इन सबने मिलकर एक नया संदेश दिया कि अब कानून केवल किताबों में नहीं, जमीन पर भी दिखेगा। आंकड़े बताते हैं कि उनके शुरुआती कार्यकाल में ही लगभग 1.5 लाख से अधिक आपराधिक मामलों का त्वरित निपटारा हुआ और 50,000 से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई। अपहरण जैसे संगठित अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई। यह केवल आंकड़े नहीं थे, यह उस मां की आंखों में लौटता हुआ विश्वास था, जो शाम ढलने पर अपने बेटे के सुरक्षित लौटने की दुआ करती थी।

जातीय संघर्षों की आग, जिसने बिहार को लंबे समय तक झुलसाया, वह भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। नरसंहारों की स्मृतियां अभी जीवित थीं। समाज टुकड़ों में बंटा हुआ था। ऐसे में उन्होंने टकराव नहीं, तटस्थता और समरसता का सेतु बनाया। 'विकास के साथ न्याय' का उनका मंत्र किसी राजनीतिक भाषण का हिस्सा नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन का सूत्र बन गया। उन्होंने महादलित आयोग का गठन किया, अति पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं चलाईं, मानो हर उस छूटे हुए हाथ को थाम लिया हो, जो वर्षों से व्यवस्था से दूर था।

नक्सलवाद वह जख्म जो बिहार के कई जिलों में गहराई तक धंसा हुआ था। वहां उन्होंने केवल सुरक्षा बलों की शक्ति नहीं, विकास की भाषा को भी उतारा। आंकड़े बताते हैं कि उनके कार्यकाल में ग्रामीण सड़कों का जाल 60,000 किलोमीटर से अधिक तक विस्तारित हुआ। यह सड़कें केवल कंक्रीट की

पट्टियां नहीं थीं, ये वे धमनियां थीं, जिनसे विकास का रक्त गांवों तक पहुंचा। जहां पहले भय था, वहां अब बसें चलने लगीं, जहां पहले बंदूक की गूंज थी, वहां अब बच्चों की किलकारियां सुनाई देने लगीं।

शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान किसी क्रांति से कम नहीं रहा। 'मुख्यमंत्री साइकिल योजना' के अंतर्गत करीब 2 करोड़ से अधिक साइकिलें छात्र-छात्राओं को वितरित की गईं। यह साइकिल केवल एक साधन नहीं थी। यह उस बेटी के सपनों का पहिया थी, जो पहली बार स्कूल की चौखट पार कर रही थी। 'पोशाक योजना' और छात्रवृत्तियों ने शिक्षा को सम्मान से जोड़ा। स्कूलों में नामांकन बढ़ा, ड्रॉपआउट दर घटी, यह सब मिलकर उस समाज का निर्माण कर रहे थे, जहां शिक्षा अब विशेषाधिकार नहीं, अधिकार बनने लगी।

महिलाओं के सशक्तिकरण में उनका निर्णय ऐतिहासिक रहा। पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण का ही सुफल है कि आज बिहार में 15 लाख से अधिक महिला जनप्रतिनिधि सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि समाज के स्वरूप का पुनर्निर्माण है कि जैसे किसी घर की चौखट, जो अब भीतर-बाहर दोनों को बराबर जोड़ती है।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या, जो पहले लाखों में सीमित थी, बढ़कर करोड़ों तक पहुंची, यह केवल संख्या का विस्तार नहीं, बल्कि विश्वास की वापसी थी।

शराबबंदी का निर्णय किसी नीति से अधिक एक पीड़ा की प्रतिक्रिया था। 2016 में लागू इस कानून ने समाज में व्यापक बहस को जन्म दिया। इसके प्रभावों पर मतभेद हो सकते हैं, पर इसकी भावना स्पष्ट थी, उस परिवार को बचाना, जो नशे की लत में टूट रहा था। यह उस मां की आंखों से आंसू पोंछने का प्रयास था, जो अपने घर को बिखरते देख रही थी।

आर्थिक दृष्टि से बिहार ने एक नई गति पकड़ी। कई वर्षों तक राज्य की विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक रही, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे थी। बिजली, सड़क, शिक्षा हर क्षेत्र में सुधार ने बिहार को पिछड़ेपन के प्रतीक से संभावनाओं के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया।

हां, इस यात्रा में विरोधाभास भी थे। गठबंधनों का बदलना, राजनीतिक समीकरणों का लचीलापन, इन सबने उन्हें आलोचना का विषय भी बनाया। परंतु यही राजनीति का वह यथार्थ है, जहां सिद्धांत और परिस्थितियों के बीच संतुलन साधना पड़ता है। नीतीश कुमार उसी संतुलन के साधक रहे। न पूरी तरह आदर्शवादी, न पूरी तरह व्यवहारवादी, बल्कि दोनों के बीच एक सेतु।

आज जब वे जा रहे हैं, तो यह वैसा ही क्षण है जैसे बेटी की विदाई। सब कुछ व्यवस्थित है, पर मन अस्त-व्यस्त है। घर खड़ा है, पर आंगन सूना है। उनके जाने के साथ केवल एक पद नहीं खाली हुआ,एक शैली, एक संस्कार, एक संतुलन भी जैसे विदा हो रहा है। यह विदाई केवल एक व्यक्ति की नहीं, एक विश्वास, एक व्यवस्था और एक पूरे युग की है।

'नीतीश कुमार होने के मायने' शायद यही हैं कि आप अराजकता में अनुशासन की अल्पना रचें, अंधकार में आशा का दीप जलाएं और बिखरते समाज को फिर से जोड़ने का धैर्य रखें।वे गए नहीं हैं, वे बस इतिहास में दर्ज हो गए हैं, जहां नाम नहीं, निशान बोलते हैं।

और अब इतिहास की सीढ़ियों पर खड़े होकर बिहार शायद धीरे से यही कह रहा है कि आप गए नहीं हैं

आप तो यहीं हैं हर सड़क में, हर स्कूल में, हर उस मां की मुस्कान में, जहां अब डर नहीं, सपने बसते हैं। ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक पहुंची सरकार

वनाधिकार पट्टा और पीएम आवास से बदली मुरिया परिवार की जिंदगी

नक्सल प्रभावित रहे बेदरे में खुशहाली की रोशनी, शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हुए बोगम भीमा

सुकमा। छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता और जनकल्याणकारी सोच का जीवंत उदाहरण सुकमा जिले के ग्राम पंचायत सिलगेर अंतर्गत आश्रित ग्राम बेदरे में देखने को मिला है। कभी घोर नक्सल प्रभावित रहे इस क्षेत्र में अब विकास और विश्वास की नई रोशनी फैल रही है। मुड़िया जनजाति के निवासी बोगम भीमा पिता हिड़मा को शासन द्वारा वनाधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, जो उनके जीवन में स्थायित्व और सम्मान की नई शुरुआत बन गया है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोगम भीमा को 1.315 हेक्टेयर वनभूमि का वनाधिकार पट्टा मिला है। वर्षों से जिस जमीन पर वे खेती कर रहे थे, वह जमीन कानूनी रूप से उनकी हो गई है। अब वे निश्चिंत होकर धान की खेती कर रहे हैं और अपने परिवार का जीवन बेहतर ढंग से चला पा रहे हैं। यह पट्टा उनके लिए केवल जमीन नहीं, बल्कि उनके अधिकार और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है। खुशियों की यह कहानी यहीं नहीं रुकी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी पत्नी को पक्का मकान भी स्वीकृत हुआ है। कभी कच्ची मिट्टी के घर में बरसात और गर्मी झेलने वाला यह परिवार अब सुरक्षित और सम्मानजनक छत के नीचे जीवन जी रहा है। वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है, जिससे उनके घर में खुशहाली और भरोसे का माहौल बना है। इसके साथ ही शासन की महतारी वंदन योजना के तहत परिवार को हर माह 1000 रुपये की सहायता राशि मिल रही है, जो उनकी दैनिक जरूरतों में बड़ा सहारा बन रही है। गांव में बिजली कनेक्शन पहुंचने से जीवन में नई सुविधा और बच्चों की पढ़ाई को नई गति मिली है। उनका बेटा आज शासकीय आश्रम छात्रावास में कक्षा 7वीं में पढ़ाई कर रहा है, जहां रहने-खाने से लेकर शिक्षा और छात्रवृत्ति तक की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन की योजनाएं अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर वास्तविक बदलाव ला रही हैं। वनाधिकार पट्टा, पक्का मकान, आर्थिक सहायता, बिजली और शिक्षा जैसी सुविधाएं बोगम भीमा के परिवार के लिए एक नए जीवन की नींव बन गई है। हितग्राही बोगम भीमा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि शासन की मदद से उनके परिवार को सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की नई उम्मीद मिली है।

लग्जरी कार में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 115 किलो गांजा जब्त, दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

केशकाल। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोंडागांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। केशकाल पुलिस ने मुस्तैदी और सतर्कता का परिचय देते हुए एक लग्जरी कार में गांजा की तस्करी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 115 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 11,52,140 रुपये बताई जा रही है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही महिंद्रा XUV 500 कार को भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपये आंकी गई है। थाना प्रभारी विकास बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा एवं एसडीओपी अरुण नेताम के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 20 अप्रैल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से रायपुर की ओर एक लग्जरी कार के जरिए गांजा की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए केशकाल थाना के सामने नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन का इंतजार किया गया। वाहन को रोकने का संकेत दिया गया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका। इस पर पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए पेट्रोलिंग वाहन और बैरिकेडिंग की मदद से कार को घेरकर रोक लिया। जांच के दौरान कार में सवार आरोपियों ने अपना नाम सूरज सिंह राठौड़ और पंकज पूरी गोस्वामी, निवासी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) बताया। तलाशी लेने पर कार की डिक्की से 53 पैकेटों में पैक गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी विकास बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम के उनि कवलसिंह शोरी, प्रेमनाथ बघेल, स.उ.नि रामकृष्ण जैन, प्र.आर. ईश्वर नेताम, अरुण मंडावी, संजय बिसेन, आरक्षक विनोद, फलेश्वर सिन्हा, धर्मेंद्र नेगी, मनोहर निषाद, कमलेश कंवर, अमित मंडावी, सदा नेताम एवं गो.स. आत्मानंद कुलदीप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अक्ति तिहार के अवसर पर माटी पूजन एवं उर्वरकों के विकल्प विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

नारायणपुर। जिले में अक्ति तिहार के पावन अवसर पर धरती माता एवं कृषि यंत्रों की पूजा-अर्चना पारंपरिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवलाल दुग्गा द्वारा माटी पूजा-अर्चना कर मुंग की बुवाई की गई। यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख एवं वैज्ञानिक डॉ. दिव्येंदु दास के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में संपन्न हुआ। साथ ही माटी पूजन के पश्चात उर्वरकों के विकल्प विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नारायणपुर अंचल के 57 ग्रामीण किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डॉ. दिव्येंदु दास (प्रमुख वैज्ञानिक) ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैविक एवं प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट, जीवामृत, घनजीवामृत आदि का उपयोग अत्यंत लाभकारी है। इसके साथ ही डॉ. आलिया अफरोज (वैज्ञानिक) ने किसानों को प्राकृतिक कीटनाशकों के निर्माण एवं उपयोग की विधियों के बारे में किसानों को विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में किसानों के समस्याओं से अवगत होकर उनके समस्याओं का समाधान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ अंकिता सिंह द्वारा किया गया। साथ ही केंद्र के वैज्ञानिकगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अक्षय तृतीया एवं राघव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के पावन अवसर पर दीप यज्ञ एवं रामचरितमानस सुंदर काण्ड पाठ का आयोजन

किरन्दुल। अक्षय पुण्य, सुख-समृद्धि एवं अनंत मंगल फल प्रदान करने वाले पावन पर्व अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर श्रीराम जन कल्याण सेवा (बैलाडीला देवस्थान) समिति और गायत्री परिवार के संयुक्त तत्वावधान में राघव मंदिर में सोमवार को संध्या 6 बजे से विविध धार्मिक आयोजन किया गया। दीप यज्ञ, सामूहिक महाआरती के पश्चात रामचरितमानस सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया गया। अक्षय तृतीया का पर्व सनातन परंपरा में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। 'अक्षय' का अर्थ होता है - जो कभी समाप्त न हो। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान-पुण्य, जप-तप और शुभ कार्यों का फल अक्षय रहता है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। इसी कारण यह दिन नए कार्यों की शुरुआत, पूजन, दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। यह अवसर इसलिए भी अत्यंत विशेष और गौरवपूर्ण है क्योंकि इसी शुभ तिथि अक्षय तृतीया के दिन श्रीराघव मंदिर की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। तब से आज तक यह पावन देवधाम नगरवासियों की अटूट श्रद्धा,आस्था, विश्वास और संस्कारों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

श्रीराघव मंदिर की स्थापना के पश्चात से ही किरंदुल में धार्मिक जागरूकता, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता को एक नई दिशा मिली है। यह मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थान नहीं, अपितु समाज में एकता, सदभाव, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का प्रेरणास्रोत भी है।

आम जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण सहित सुशासन तिहार की करें तैयारी: कलेक्टर आकाश छिकारा

जगदलपुर। कलेक्टर आकाश छिकारा ने कहा कि सुशासन तिहार का आयोजन मई माह से किया जाएगा इसकी आवश्यक तैयारियों के साथ ही आम जनता के विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण एवं लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना सुनिश्चित करें। जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की कार्यों और योजनाओं प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि 1 मई से प्रारंभ होने वाले सुशासन तिहार से पूर्व शासन के विभिन्न पोर्टलों-सीएम हेल्पलाइन, पीजी पोर्टल, जनदर्शन एवं राजस्व प्रकरणों में प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण कर लिया जाए। साथ ही हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित भुगतान की राशि वितरण तथा मूलभूत संरचना से संबंधित आवेदनों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नियद नेल्लनार योजना 2.0 और बस्तर मुन्ने के शिविरों में लक्षित योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। 24 अप्रैल को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में ग्राम विकास से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा करने तथा जिले में प्रस्तावित सुशासन तिहार के शिविरों की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत स्क्रीनिंग की दर बढ़ाने, लक्ष्य आधारित स्वास्थ्य जांच करने तथा आवश्यकतानुसार मरीजों को उच्च संस्थानों में रेफर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य अमले को प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया गया। बैठक में धान उपार्जन केंद्रों से 30 अप्रैल तक धान का उठाव सुनिश्चित करने, चावल भंडारण की स्थिति, एपीसी बैठक की तैयारियों, नक्शा बंटांकन, असर्वेक्षित गांवों के प्रकरण, स्वामित्व योजना तथा पीएम आवास योजना (शहरी) के लंबित कार्यों की ऑनलाइन प्रविष्टि कराने की समीक्षा की गई। इसके अलावा जनगणना के लिए स्व-गणना भरने, निष्क्रिय खातों की राशि शासन के खातों में जमा कराने, संपूर्णता अभियान 2.0, हाउसिंग बोर्ड के निर्माण कार्यों की प्रगति तथा आयुष्मान कार्ड की स्थिति की भी समीक्षा की गई। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के पेंशन प्रकरणों को तैयारी, एनक्यूएएस प्रमाणन हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, रेड कॉल सेंटर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए बढ़ावा देने पर चर्चा किए। बैठक में पीएम योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति, एनआरसी में बच्चों की उपस्थिति तथा स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत एनसीडी स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अंत में कलेक्टर ने जनदर्शन में नागरिकों से आवेदन लेकर अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान वन मंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर सोपी बघेल, ऋषिकेश तिवारी, सहायक कलेक्टर विपिन दुबे सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टोरेट में शासकीय कबाड़ की खुली बिक्री, तांबा और पीतल समेत कई सामग्रियों के दाम तय

जगदलपुर। कलेक्टोरेट जगदलपुर के राजस्व विभाग के अंतर्गत नाजरात शाखा में जमा अनुपयोगी शासकीय सामग्रियों को अब कबाड़ के रूप में बेचा जा रहा है। जारी सूचना के अनुसार इन सामग्रियों का विक्रय प्रति किलोग्राम की निर्धारित दर पर किया जाएगा, जिसमें सबसे कीमती स्क्रैप कॉपर है जिसकी दर 246 रुपए प्रति किलो तय की गई है। इसके अतिरिक्त स्क्रैप ब्रॉस 144 रुपए, एल्यूमिनियम 82 रुपए, स्क्रैप आयरन 28 रुपए और जीआई पाइप 25 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध हैं। कम कीमत वाली श्रेणियों में टीन 15 रुपए, वाहन टायर और पुराने कागज 08 रुपए तथा प्लास्टिक मात्र 05 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन प्रस्तुत कर जिला कार्यालय के जिला नाजिर से संपर्क कर सकते हैं और निर्धारित दरों पर सामग्री का क्रय कर सकते हैं। सामग्रियों के नाप-तौल और कागज स्क्रैपिंग मशीन की पूरी व्यवस्था आवेदक को स्वयं के खर्च पर करनी होगी। साथ ही सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से यह नियम बनाया गया है कि क्रय की गई कबाड़ सामग्री का उठाव तभी संभव होगा जब उसकी पूरी राशि शासन के पास जमा कर दी जाएगी।

मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल को

कांकेर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल को किया जाएगा। यह परीक्षा राज्य के 16 जिलों में आयोजित होगी, जिसमें लगभग 02 लाख 47 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। कांकेर जिले में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए है, जिसमें 11811 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा परीक्षार्थियों के लिए जारी दिशा-निर्देशानुसार उक्त परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन करने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 02 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार 9.30 बजे बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। व्यापमं द्वारा जारी निर्देशानुसार परीक्षार्थियों से कहा गया है कि वे हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें और कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित किया गया है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

मंडी बोर्ड उप निरीक्षक परीक्षा हेतु 46 केंद्रों में 12 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आगामी 26 अप्रैल को आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियां जिले में अंतिम चरण पर है। इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए कलेक्टर आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में जगदलपुर में कुल 46 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 12,136 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि यह परीक्षा प्रदेश के चुनिंदा 16 जिलों में आयोजित की जा रही है, लेकिन इसमें सभी 33 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा की समय-सारणी के अनुसार यह लिखित परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक संचालित होगी। सुरक्षा और सत्यापन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, ताकि उनकी सघन तलाशी (फ्रिस्किंग) और फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से मिलान किया जा सके। समय की पाबंदी को लेकर निर्देश अत्यंत सख्त हैंय परीक्षा केंद्रों का मुख्य द्वार ठीक सुबह 9.30 बजे बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद पहुंचने वाले किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए परीक्षा से एक दिन पहले अपने आबंटित केंद्र का अवलोकन अवश्य कर लें।

समय-सीमा की बैठक संपन्न : बस्तर मुन्ने, सुशासन तिहार और नियद नेल्लनार 2.0 की करें तैयारी: कलेक्टर अमित

सुकमा। एकलेक्टर अमित कुमार ने कहा कि सुशासन तिहार का आयोजन मई माह से किया जाएगा इसकी आवश्यक तैयारियों के साथ ही आम जनता के विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण एवं लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना सुनिश्चित करें। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि 1 मई से प्रारंभ होने वाले सुशासन तिहार से पूर्व शासन के विभिन्न पोर्टलों-सीएम हेल्पलाइन, पीजी पोर्टल, जनदर्शन एवं राजस्व प्रकरणों में प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण कर लिया जाए। साथ ही हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित भुगतान की राशि वितरण तथा मूलभूत संरचना से संबंधित आवेदनों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए गए।

डीएवी गारका 10वीं के मेधावी विद्यार्थियों को कलेक्टर व एसपी ने किया सम्मानित

केशकाल। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में DAV MMPS गारका के होनहार विद्यार्थी रागनी जैन, मालनी बौद्ध, वंशिका ख्वास, भूमि साहसी, साजिया जिलानी एवं सुफियान पारेख को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया। जिला कलेक्टर ने मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कलेक्टर ने विद्यार्थियों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करते हुए उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी और उनके अनुभव भी जाने। कलेक्टर ने बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, अनुशासन एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे भी इसी लगन और समर्पण के साथ अध्ययन करते रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के अन्य छात्र-छात्राएं भी इनसे प्रेरणा लेकर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करें। कार्यक्रम में अभिभावकों एवं शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना की गई, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से विद्यार्थियों ने यह उपलब्धि हासिल की। विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकगण ने भी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

हल्के रंग के कपड़े अनिवार्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित कई वस्तुओं पर प्रतिबंध

उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026: समय, ड्रेस कोड एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

सुबह 9:30 बजे बंद होंगे केंद्र के द्वार, 10:00 से 12:15 बजे तक परीक्षा

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत आयोजित होने वाली उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के सुचारू संचालन के लिए अभ्यर्थियों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह परीक्षा 26 अप्रैल को प्रदेश के 16 जिलों में आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 2 लाख 47 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में राज्य के सभी 33 जिलों के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।

समय एवं प्रवेश संबंधी निर्देश

परीक्षा का आयोजन प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार सुबह 9:30 बजे बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को कम से कम 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। साथ ही, परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का अवलोकन करने की सलाह दी गई है।

ड्रेस कोड संबंधी निर्देश

अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र आना होगा।

काले, गहरे नीले, हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी एवं गहरे चॉकलेटी रंग के वस्त्र पहनना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिधान पहनने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पूर्व पहुंचकर अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। फुटवियर के रूप में केवल चप्पल पहनने की अनुमति होगी तथा कानों में किसी भी प्रकार के आभूषण वर्जित रहेंगे।

प्रतिबंधित वस्तुएं एवं सामग्री

परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अभ्यर्थियों को केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी।

अनुशासन एवं आवश्यक निर्देश

अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें तथा परीक्षा को सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें।

संक्षिप्त समाचार

संगठन सृजन के तहत बूथ,वार्ड कमेटी के गठन फदहाखार में

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के दिशा निर्देश एवं जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री , विजय केसरवानी पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलतरा मंडल मटियारी के अंतर्गत फदहाखार में धनंजय सिंह ठाकुर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलतरा, जगदीश कौशिक कांग्रेस नेता, शीतल दास मानिकपुरी समन्वयक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर ग्रामीण बेलतरा इब्राहिम खानअब्दुल खान पार्षद के उपस्थिति में संगठन सृजन अभियान के तहत बूथ, वार्ड कमेटी का गठन किया गया, इस अवसर पर माननीय धनंजय सिंह ठाकुर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलतरा, जगदीश कौशिक कांग्रेस नेता, शीतल दास मानिकपुरी समन्वयक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर ग्रामीण बेलतरा, इब्राहिम खान अब्दुल पार्षद, समाज सुल्तान कांग्रेस नेता बजरंग साहू, अजय खूटे, प्रमोद यादव धनसाय पात्रे, असर दास जांगड़े प्रकाश साहू मोहम्मद अहमद खान,सोसन कनडुलना, मलती कुजुर, सुचिता तिग्गा, गंगोत्री बाई,सुनीता रजक, सत्या तिर्की, गीता साहू,तीजन बाई, अनीता सिंह, गायत्री पाटले, गीता कुक, संतोषी गोस्वामी आदि सैकड़ो की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता गन उपस्थित रहे।

स्काउट-गाइड्स के बच्चों ने शुरू किया प्याऊ घर भीषण गर्मी में राहगीरों व श्रमिकों को मिलेगी राहत

बिलासपुर । जिले में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए रियल ग्रोथ पब्लिक उरलापुर के स्काउट-गाइड के बच्चों द्वारा समाज सेवा की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए उरलापुर ओवर ब्रिज के नीचे प्याऊ घर का शुभारंभ किया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से राहगीरों, श्रमिकों और आमजन को निःशुल्क शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ वार्ड पार्षद राजेंद्र किरण टंडन द्वारा गया। इस अवसर पर जिला मुख्य आयुक्त चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट) महेन्द्र बाबू टंडन, चेयरमैन डी.के.जायसवाल, एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती दिलजीत कौर छाबड़ा, डायरेक्टर श्रीमती तनिष्का जायसवाल, उप प्राचार्या सुश्री ऊषा मिश्रा तथा शाला की गाइडर श्रीमती पुष्पा शर्मा सहित विद्यालय परिवार के सदस्य एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। इस दौरान जिले के स्काउट्स-गाइड्स, रोवर-रेंजर एवं स्काउटर-गाइडर ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और सेवा कार्य में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भीषण गर्मी में इस प्रकार की व्यवस्था आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी और विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करेगी। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि प्याऊ घर के माध्यम से प्रतिदिन राहगीरों को स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही स्काउट-गाइड के छात्र-छात्राएं नियमित रूप से यहां सेवा कार्य करते हुए लोगों को जल पिलाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों ने इस जनसेवा कार्य को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया और विद्यालय के इस प्रयास की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

3147 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट का काम शुरू

पत्थलगांव-झारखंड सीमा तक सड़क निर्माण ने पकड़ी गति

■ रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब धरातल पर

बिलासपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती पर रखी गई आधारशिला अब धरातल पर उतर आई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पत्थलगांव-कुनकुरी से छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा (ह्॥-43) तक 3147 करोड़ रूपये की लागत वाले मेगा परियोजना का निर्माण कार्य जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा विस्तार- 627 किलोमीटर लंबे रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण और विशाल हिस्सा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। कुल लंबाई का लगभग 384 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान में 104.250 किलोमीटर लंबे पत्थलगांव-झारखंड सीमा खंड पर निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। 382 छोटी-बड़ी संरचनाएं- इस खंड में कुल 382 छोटी-बड़ी संरचनाएं (पुल, अंडरपास आदि) बनाई जाएंगी, जो इस मार्ग को बाधारहित बनाएंगी। जिसमें 7 बड़े पुल, 30 छोटे पुल, 6 फ्लाईओवर और एक एलीवेटेड वायडक्ट स्ट्रक्चर, 10 वेहिकुलर अंडरपास 18 लाइट वेहिकुलर अंडरपास 26 स्मॉल वेहिकुलर अंडरपास , 11 ईओपी, 21 मवेशी एवं पैदल यात्री अंडरपास और 278 बॉक्स पुलिया का निर्माण किया जा रहा है इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी होगी मजबूत- कोरबा परियोजना इकाई के परियोजना निदेशक डी.डी. पार्लावर ने बताया कि यह खंड रायपुर-धनबाद कॉरिडोर की रीढ़ है जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हमारा लक्ष्य इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना है। यह राजमार्ग छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी और व्यापारिक परिवहन को नई मजबूती देगा। जशपुर जिले की बदलेगी तकदीर- यह कॉरिडोर जशपुर जिले के लिए केवल सड़क नहीं, बल्कि लाइफलाइन साबित होगा। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह अंचल के महत्वपूर्ण नगरों- पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, दुलदुला और जशपुर को एक सूत्र में पिरोएगा। साथ ही, यह राजमार्ग रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा जैसे औद्योगिक शहरों को सीधे झारखंड के धनबाद से जोड़कर व्यापारिक सुगमता प्रदान करेगा। तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी- तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप ईंधन, यात्रा समय और कुल परिवहन लागत में बचत होगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कोयला खदानों एवं कोरबा, रायगढ़, जशपुर, रांची और जमशेदपुर में स्थित प्रमुख इस्पात संयंत्रों के लिए बेहतर अंतर-राज्यीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यातायात में सुगम आवागमन एवं दुर्घटनाओं और प्रदूषण में कमी होगी। वस्तुओं और खनिजों के कुशल परिवहन से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार व व्यावसायिक अवसरों का सृजन होगा।

बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने चलाया जा रहा है सघन टिकट जांच अभियान

■ मंडल के चांपा एवं शहडोल स्टेशनों में किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान से 02 लाख 54 हजार 555 रुपये का वसूला गया जुर्माना

बिलासपुर । बिलासपुर मंडल वाणिज्य विभाग द्वारा बिना टिकट यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण एवं यात्रियों में वैध टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सघन टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में ट्रेनों तथा स्टेशनों पर टिकट जांच को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना के तहत चलाई जा रही हैइस अभियान के तहत सहायक वाणिज्य प्रबंधक श्री डी.एस. चौहान के नेतृत्व में मंडल के शहडोल और चांपा स्टेशन तथा गाड़ियों में किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में वाणिज्य निरीक्षक, मुख्य टिकट निरीक्षक एवं टीटीई स्टाफकी सक्रिय भागीदारी रही। इन दोनों स्टेशन में चलाये गए अभियान में कुल 506 मामलों में 02 लाख 54 हजार 555 रुपये बतौर जुर्माना वसूले गए । चाम्पा स्टेशन में चलाये गए अभियान में बिना टिकट यात्रा के 218 मामलों से 1,44,230 रुपये, अनियमित टिकट के 63 मामलों से 25,325 रुपये, बिना बुक किए गए लगेज के 63 मामलों से 6,300 रुपये एवं गंदगी फैलाने के 5 मामलों से 500 रुपये का जुर्माना शामिल है। इसी प्रकार शहडोल स्टेशन में चलाये गए टिकट जांच में बिना टिकट यात्रा के 146 मामलों से 76,600 रुपये, बिना बुक किए गए लगेज के 07 मामलों से 1,200 रुपये एवं गंदगी फैलाने के 4 मामलों से 400 रुपये का जुर्माना शामिल है।

डाक विभाग ने चार मार्गों में किया गया आरटीएन सेवा का शुभारंभ....

ग्रामीणों को मिलेगा डाक सेवा का अधिकतम लाभ

बिलासपुर। भारतीय डाक विभाग, बिलासपुर ने रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (आरटीएन) सेवा के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 18 अप्रैल 2026 से जिले के चार नए क्षेत्रों में आरटीएन सेवा का शुभारंभ किया गया, जिससे डाक संचार और अधिक सुदृढ़ एवं तेज हो सकेगा। बिलासपुर आरएमएस (रेल डाक सेवा) से लोरमी, जैजैपुर, मरवाही और भैसमा उप डाकघर तक आरटीएन सेवा प्रारंभ की गई है। इससे इन क्षेत्रों में डाक के त्वरित आदान-प्रदान, ट्रैकिंग और डिलीवरी में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। बिलासपुर आरएमएस से लोरमी उप डाकघर तक के लिए रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में बिलासपुर आरएस, चकरभाठा, बिल्हा, पथरिया, तखपुर और मुंगेली जोड़ा गया है। वहीं, जैजैपुर उप डाकघर के लिए मस्तुरी, जयरामनगर, गोपालनगर, नरियरा, पामगढ़, खरोद, शिवरीनारायण, बिर्रा, बम्हनी बाजार, जैजैपुर शामिल हैं। मरवाही उप डाकघर के लिए सकरी, गनियारी, करगी रोड, बेलगहना, पेंड्रा रोड, पेंड्रा और मरवाही को शामिल किया गया है। भैसमा उप डाकघर के लिए कोनी, रतनपुर, पाली, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, जमनीपाली, बालको नगर, कोरबा एचओ और भेसमा को रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में जोड़ा गया है। इसी प्रकार चंद्रपुर एवं डब्ल्यूसीएल गेवरा मार्ग के लिए भी आरटीएन सेवा शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। डाक विभाग ने इस विस्तार से क्षेत्रीय स्तर पर डाक सेवाओं की निगरानी, पार्सल और स्पीड पोस्ट की डिलीवरी, स्थानीय व्यापार और ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा।

विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए टीम गठित

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में 5 मई से 20 मई 2026 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान संचालित किया जाएगा, जिसके माध्यम से किसानों को खरीफ सीजन की तैयारी एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अभियान के सफल आयोजन के लिए टीम गठित कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। यह टीम सभी विकासखण्डों में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करेगी। इस अभियान के सफल संचालन के लिए विभाग ने अलग-अलग विकासखंडों के लिए विशेषज्ञों की दो-दो टीम गठित की है। बिल्हा विकासखंड में कृषि विज्ञान केंद्र की विशेषज्ञ डॉ. शिल्पा कौशिक, डॉ. स्वाति शर्मा, एडीओ श्री डी.पी. दिवाकर और श्री सी.पी. ध्रुवे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। मस्तूरी क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ श्रीमती हेमकांति बंजारे, डॉ. निवेदिता पाठक, एडीओ श्री के.एस. मार्को और श्रीमती अनामिका वर्मा की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार तखतपुर विकासखंड में विशेषज्ञ डॉ. एकता ताम्रकार, डॉ. चंचला रानी पटेल, एडीओ श्रीमती शिल्पा श्रीवास्तव और श्रीमती उषा बैरहा खाण्डे किसानों का मार्गदर्शन करेंगे। कोटा विकासखंड के लिए गठित टीमों में विशेषज्ञ डॉ. अमित कुमार शुक्ला, डॉ. विनोद निर्मलकर, एडीओ श्री डी.के. राते और श्री मनोज कुमार सिंह अपनी सेवाएं देंगे। इन टीमों के साथ कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य और पशुपालन विभाग के अधिकारी भी तैनात रहेंगे। यह अभियान सीधे तौर पर किसानों को उन्नत बीज, पशुपालन और मछली पालन की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराएगा।

अटल बिहारी वाजपेयी विवि में बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती की प्रतिमाओं का अनावरण किया

बिलासपुर । अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कोनी स्थित नवीन अकादमिक सह प्रशासनिक भवन परिसर में एक ऐसा आयोजन संपन्न हुआ, जो इतिहास के गौरव को वर्तमान की कार्ययोजना से जोड़ने का एक वैचारिक प्रयास है। महान स्वतंत्रता सेनानी 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा और अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती की प्रतिमाओं का भव्य अनावरण, विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक दृष्टि के पुनर्जागरण का प्रतीक सिद्ध हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कुलपति प्रो. (डॉ.) एल.पी. पटेरिया ने प्रतिमाओं का अनावरण करते हुए इसे मात्र एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि वैचारिक धरोहर के संरक्षण का संकल्प बताया। कुलपति ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया कि इन महानायकों का जीवन 'इतिहास' नहीं, बल्कि 'वर्तमान' की प्रेरणा है। उन्होंने रामचरितमानस की कालजयी चौपाई परहित सरिस धरम नहि भाई, पर पीड़ा सम नहि अधमाई का स्मरण करते हुए कहा कि जनजातीय अस्मिता और नारी शक्ति का यह संगम, विश्वविद्यालय के शोध और लेखन का प्रमुख केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि नई पीढ़ी इन महानायकों के संघर्ष को अकादमिक शोध के माध्यम से पुनर्जीवित करे। कुलसचिव तरणीश गौतम ने इस आयोजन को विश्वविद्यालय की 'सांस्कृतिक रीढ़' को मजबूत करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक दायित्व की भावना का विकास तभी संभव है, जब शिक्षण संस्थाएँ इतिहास के इन प्रकाश-स्तंभों को अपनी दिनचर्या और परिसर का अभिन्न अंग बनाएँ। अकादमिक जगत के प्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। कंप्यूटर साइंस विभाग के अधिष्ठाता डॉ. एच.एस. होता ने तकनीकी शिक्षा के साथ ऐतिहासिक चेतना के सामंजस्य पर बल दिया, वहीं वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता डॉ. अतुल दुबे ने इसे नेतृत्व क्षमता के पाठ के रूप में रेखांकित किया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधिष्ठाता डॉ. कलाधर ने इस आयोजन को युवा पीढ़ी में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को नई दिशा देने वाला बताया। विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के कुशल समन्वय और परिसर की स्वच्छता व अनुशासन ने इस पूरे आयोजन को एक अत्यंत गरिमामय और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया।

छुट्टियों के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष ट्रेनों का व्यापक संचालन

■ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 18 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें, कुल 88 ट्रिप का किया जा रहा है संचालित

■ ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की बढ़ी हुई उपलब्धता से यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी, प्रतीक्षा सूची कम होगी और गर्मियों की भीड़भाड़ के दौरान लाखों यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित होगी

बिलासपुर । भारतीय रेलवे द्वारा ग्रीष्म ऋतु 2026 के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए देशभर में विशेष ट्रेनों का व्यापक संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 15 अप्रैल, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक की अवधि के लिए कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों को मंजूरी प्रदान की गई है, जो इस अवधि में 18,262 ट्रिप संचालित करेंगी । यह पहल गर्मियों के चरम समय में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और प्रतीक्षा सूची को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से कुल 18 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों को मंजूरी दी गई है, जो यात्रियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 88 ट्रिप संचालित करेंगी । इनमें से 13 विशेष ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है, जबकि शेष 75 ट्रिप आगामी दिनों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किए जाएंगे । इन विशेष ट्रेनों का संचालन विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के बीच किया जाएगा, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा । इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा भी यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं । क्षेत्र के प्रमुख एवं व्यस्त स्टेशनों जैसे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, इतवारी, रायगढ़ एवं शहडोल सहित अन्य महत्वपूर्ण

स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। इनमें प्लेटफॉर्म प्रबंधन, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालयों में सुधार, स्वच्छता व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की बढ़ी हुई उपलब्धता से यात्रियों को कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। इससे न केवल ट्रेनों में भीड़भाड़ कम होगी, बल्कि प्रतीक्षा सूची में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही, यात्रियों को समय पर आरक्षण मिलने से उनकी यात्रा अधिक सुविधाजनक एवं तनावमुक्त होगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लाखों यात्रियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, जो गर्मी के मौसम में अपने गंतव्य तक यात्रा करते हैं । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा अधिकृत माध्यमों से ही टिकट आरक्षित करें। रेलवे प्रशासन यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। जिसकी जानकारी इस प्रकार है :- गाड़ी संख्या 08743 दुर्ग-हरिद्वार साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन दुर्ग से प्रत्येक रविवार को 26 अप्रैल से 28 जून, 2026 तक परिचालन होगा । गाड़ी संख्या 08744 हरिद्वार-दुर्ग साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन हरिद्वार से प्रत्येक सोमवार को 27 अप्रैल से 29 जून, 2026 तक परिचालन होगा । गाड़ी संख्या 08865 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-शालीमार साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रत्येक गुरुवार को 23 अप्रैल से 25 जून, 2026 तक परिचालन होगा । गाड़ी संख्या 08866 शालीमार-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रत्येक शुक्रवार को 24 अप्रैल से 26 जून, 2026 तक परिचालन होगा । गाड़ी संख्या 08867 गोंदिया-रक्सौल साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन गोंदिया से प्रत्येक शनिवार को 25 अप्रैल से 27 जून, 2026 तक परिचालन होगा । गाड़ी संख्या 08868 रक्सौल-गोंदिया साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन गोंदिया से प्रत्येक रविवार को 26 अप्रैल से 28 जून, 2026 तक परिचालन होगा । गाड़ी संख्या 08871 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-मालदा समर स्पेशल ट्रेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 26 अप्रैल, 2026 को परिचालन होगा गाड़ी संख्या 08872 मालदा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) समर स्पेशल ट्रेन मालदा से 27 अप्रैल, 2026 को परिचालन होगा ।

गांव चलो अभियान संगठन सृजन के तहत ग्राम पंचायत लगरा में पंचायत कांग्रेस कमेटी एवं बूथ कांग्रेस कमेटी का गठन

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस माननीय अध्यक्ष दीपक बैज जी के दिशा निर्देश जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, विजय केसरवानी पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र बेलतरा के मार्गदर्शन में संगठन सृजन के तहत ग्राम पंचायत लगरा में बूथ कांग्रेस कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन धनंजय सिंह ठाकुर अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलतरा, शीतल दास मानिकपुरी समन्वयक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलतरा के उपस्थिति में किया गया इस अवसर पर माननीय प्रवेश पटवा प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग,शिव शंकर केवट, कृष्ण कुमार यादव, राजकुमार श्रीवास,उमेश कुमार केवट,सुनील यादव, रमेश पटेल, सुनील केवट आदि कांग्रेस कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

हिंदू धर्म में मां गंगा की पूजा का विशेष महत्व

गंगा सप्तमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। गंगा सप्तमी को गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस बार सप्तमी तिथि का संयोग दो दिन होने के कारण 22 और 23 अप्रैल दिन गंगा सप्तमी मनाई जाएगी इसे लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है। आइए जानते हैं पंड़ित राकेश झा से किस दिन गंगा सप्तमी मनाना शुभ रहेगा।

गंगा सप्तमी कब है

गंगा सप्तमी तिथि का आरंभ 22 अप्रैल को रात में 10 बजकर 50 मिनट पर होगा और 23 अप्रैल को रात में 8 बजकर 50 मिनट पर तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार, सप्तमी तिथि 23 अप्रैल को रहने के कारण इसी दिन गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन कई लोग व्रत और पूजा भी करते हैं।

गंगा सप्तमी के दिन क्या करें

इस दिन सुबह जल्दी उठे इसके बाद गंगा में स्नान करें। अगर गंगा में स्नान नहीं कर पा रहें है तो घर में ही पानी में थोड़ी गंगाजल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद एक तांबे के लौचे में पानी लें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर में बैठकर मां गंगा के मंत्र ओम नमो गंगायै विश्वरुपिणी नारायणी नमो नम:का जप करें। इसके अलावा इस दिन जरुरतमंद लोगों को मौसमी फल या बाकी चीजों का दान जरुर करें। इस दिन दान करने से दोगुना फल प्राप्त होता है।

गंगा सप्तमी पर विशेष उपाय

गंगा स्नान का विशेष महत्व है, विशेषकर वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन, जब मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पुण्य कार्य करने से सभी पाप समाप्त होते हैं इस तिथि पर गंगा स्नान, तप और दान-पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा पूजन करने से मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्तियों को विशेष लाभ मिलता है। विधिपूर्वक किया गया गंगा का पूजन अमोघ फल देता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से दस पापों का नाश होता है और अंतत: मुक्ति प्राप्त होती है। गंगा सप्तमी के अवसर पर मां गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। इस पर्व के अवसर पर गंगा मंदिरों के साथ-साथ अन्य मंदिरों में भी विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा की पूजा और स्नान करने से रिद्धि-सिद्धि तथा यश-सम्मान की प्राप्ति होती है।

लू लगने पर भूलकर भी ना करें ये गलतियां

बढ़ता तापमान बच्चे हों या बड़े, सभी के लिए सेहत से जुड़ी समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में लोगों को सबसे ज्यादा लू लगने का खतरा बना रहता है। लू से बचाव कैसे करें, इसके बारे में तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए, ऐसी स्थिति में उसे कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए।

लक्षण नजरअंदाज करना

लोग सबसे ज्यादा यही गलती कर बैठते हैं। अगर आपको चक्कर आना, तेज सिरदर्द, उल्टी, या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उन्हें हल्के में ना लें। ये सभी लक्षण लू का संकेत हो सकते हैं। ऐसे में लू के लक्षण दिखते ही तुरंत उपचार के लिए चिकित्सा सहायता लें।

गर्मी में रहना

लू लगने के बाद भी कुछ लोग सारा दिन तेज धूप और गर्मी में समय बिताते हैं। ऐसी गलती ना करें। मरीज को लू लगने पर तुरंत छायादार या ऐसी वातानुकूलित जगह पर ले जाना चाहिए, जहां उसे गर्मी ना लगे।

पानी न पीना या गलत पेय पीना

कुछ लोग लू लगने के बावजूद पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं बल्कि इसकी जगह कैफीनयुक्त या अल्कोहल का सेवन करने लगते हैं। ऐसी गलती ना करें। लू लगने पर रोगी को हमेशा ठंडा पानी या ओआरएस का घोल धीरे-धीरे पिलाएं। शराब, कॉफी या सोडा का सेवन करने से बचें।

गलत दवा लेना

कई बार लोग लू के बुखार को कम करने के लिए एस्पिरिन या पैरासिटामॉल जैसी दवाएं खाने लगते हैं। यह गलती ना करें। लू में ये दवाएं फायदे की जगह नुकसान कर सकती हैं। लू लगने पर सिर्फ डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी दवा का सेवन करें।

शरीर का तापमान कम ना करना

कई बार लोग लू लगने पर मरीज के शरीर का तापमान कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। जबकि सबसे पहले यही करना चाहिए। ध्यान रखें, लू लगने पर सबसे पहले शरीर को गीले कपड़े से पोंछें, पंखे या एसी चलाएं, रोगी को ठंडे पानी से स्नान करवाएं लेकिन ऐसा करते हुए बर्फ को सीधे त्वचा पर न लगाएं।

भारी कपड़े पहने रहना

कई बार रोगी टाइट या भारी कपड़े पहने रहता है, जो शरीर की गर्मी को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में लू से बचाव करने के लिए भारी मोटे कपड़ों की जगह हल्के-ढीले कपड़े पहने ताकि शरीर ठंडा रह सके।

डॉक्टरी मदद में देरी

लू के गंभीर लक्षण जैसे बेहोशी या तेज बुखार होने के बावजूद भी डॉक्टर के पास न जाना। कई लोग दवाओं से ज्यादा घरेलू उपचार पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन लू के लक्षण अगर गंभीर हों (जैसे बुखार 104°F से अधिक, भ्रम, या दौरे), तो तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। घर पर रहकर अपना इलाज खुद करने की गलती ना करें।

कैंसर के आधुनिक इलाज में नई दिशा

एच सीजी कैंसर अस्पताल, बोरिवली ने उन्नत रोबोटिक कैंसर देखभाल को अधिक सटीक, प्रभावी और सुलभ बनाने पर चर्चा की एचसीजी कैंसर अस्पताल, बोरिवली ने सफलतापूर्वक रोबोकॅन (ROBOCAN) 1.0 का आयोजन किया। यह "रोबोटिक सर्जरी: रोबोटिक उत्कृष्टता के साथ कैंसर देखभाल की नई परिभाषा" विषय पर एक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन (CME) सत्र था। इस कार्यक्रम में प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने कैंसर उपचार में रोबोटिक-सहायता प्राप्त सर्जरी की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की।

इस सत्र का उद्देश्य विलनिकल समझ को मजबूत करना और न्यूनतम इनवेरिव तथा राटीक सर्जिकल तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना था। चर्चा में यूरोलॉजी, हेड एंड नेक कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर और स्त्री रोग ऑन्कोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी सटीकता बढ़ाती है, जटिलताओं को कम करती है और मरीजों की रिकवरी को तेज बनाती है। डॉ. साकेत साठे ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी ने यूरोलॉजिकल कैंसर उपचार में बड़ा बदलाव लाया है। डॉ. चंद्रकांत पंचोली ने कहा कि यह तकनीक अधिक सुरक्षित और प्रभावी सर्जिकल हस्तक्षेप संभव बनाती है। डॉ. तीरथराम कौशिक ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी अब जटिल मामलों में भी उपयोगी साबित हो रही है। हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी में BABA तकनीक पर विशेष जोर दिया गया। डॉ. यश माथुर ने कहा कि इस तकनीक से सर्जरी के बाद विकृति कम होती है। श्री अविक चौहान ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी कैंसर उपचार को अधिक मरीज-केंद्रित बना रही है। कार्यक्रम का समापन पैनल चर्चा के साथ हुआ।

आपके वेडिंग लुक पर चार चांद लगा देंगे ये ब्लाउज डिजाइन

गर्मियों में शादियों का सीजन आते ही महिलाएं अपनी साड़ियों और लहंगों के साथ स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन की तलाश शुरू कर देती हैं। इस बार ब्लाउज डिजाइन में कई नए और अट्रैक्टिव ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट फ्यूजन पेश करेंगे। ऐसे में हल्के और सांस लेने वाले फैब्रिक्स, खूबसूरत एंब्रॉयडरी और इनोवेटिव पैटर्न इस वेडिंग सीजन के ब्लाउज को खास बनाएंगे। यहां कुछ ऐसे ही लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन के बारे में बताए गए हैं, जो शादियों में आपके लुक को काफी स्टाइलिश बना देंगे।

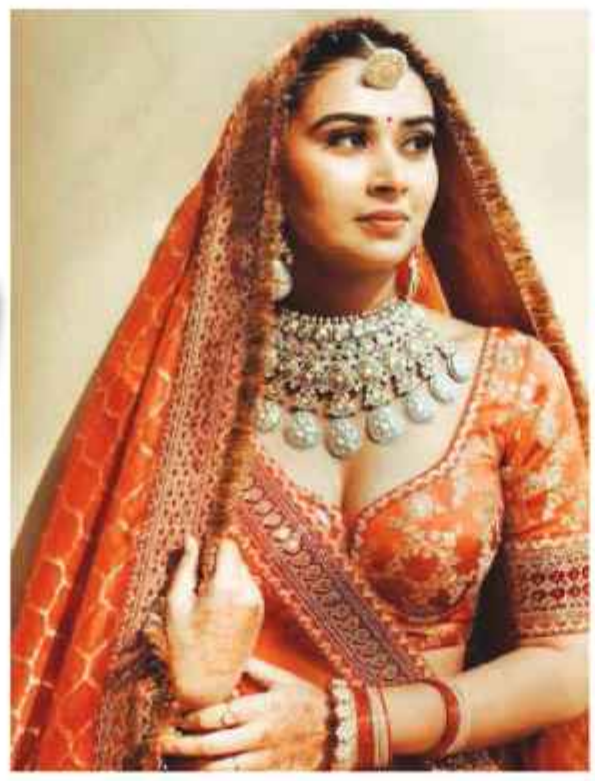

शीयर स्लीव्स और नेट ब्लाउज- शियर और नेट ब्लाउज डिजाइन इस साल दुल्हनों और शादी में शामिल होने वाली महिलाओं की पहली पसंद बने रहेंगे। हल्की एंब्रॉयडरी और स्टोन वर्क से सजे ये ब्लाउज समर वेडिंग्स के लिए बेस्ट चॉइस होते है।

स्लीवलेस और हॉल्टर नेक डिजाइन- गर्मी के मौसम में हॉल्टर नेक और स्लीवलेस ब्लाउज का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ये स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन मॉडर्न लुक को पसंद करने वाली महिलाओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हैं।

फुल स्लीव्स विद हेवी एंब्रॉयडरी- अगर आप गर्मियों में भी ग्रेसफुल और क्लासी लुक चाहती हैं, तो फुल स्लीव्स वाले हेवी एंब्रॉयडरी ब्लाउज बेस्ट ऑप्शन हैं, जो एसी हॉल में होने वाली वेडिंग्स में शाही अंदाज में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं।

डीप बैक विद डोरी और टैसल्स

इस बार खास तौर पर डीप बैक ब्लाउज डिजाइन खासतौर पर ट्रेंड में रहेंगे। इन ब्लाउज के पीछे डोरी और टैसल्स का खूबसूरत कॉम्बिनेशन ब्राइडल और गेस्ट लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा।

क्या होता है ऑरेंज, रेड अलर्ट

भीषण गर्मी हो या सर्दी की लहर आपने अकसर टीवी, मोबाइल पर न्यूज देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) को मौसम संबंधी जानकारी और चेतावनियां देते हुए कई बार सुना होगा। बता दें, आईएमडी मौसम से जुड़ी गंभीरता और संभावित प्रभावों को बताने के लिए चार रंग के कोड का यूज करता है। ये सभी चारों रंग के कोड देश में बारिश, चक्रवात, तूफान, गर्मी, बर्फबारी जैसी स्थिति की जानकारी देने के लिए जारी किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन से रंग का कोड किस चेतावनी की तरफ इशारा करता है। अगर नहीं, तो आपको बताते हैं किस रंग के कोड का क्या मतलब होता है।

हरा रंग

- आईएमडी के हरे रंग के कोड का मतलब होता है कि सब ठीक है। यह रंग बताता है कि मौसम की सामान्य स्थिति बनी हुई है। किसी तरह का कोई खतरा नहीं होने की वजह से किसी तरह की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

लाल रंग

- लाल रंग के कलर कोड का मतलब होता है कि तुरंत कार्रवाई करें। इसका मतलब होता है कि मौसम की स्थिति अत्यंत गंभीर है, जो रुकावट, बिजली आपूर्ति में व्यवधान जैसी समस्याओं के लिए व्यक्ति को पहले से ही तैयार रहने के लिए अलर्ट करता है। उदाहरण के लिए आपदा प्रबंधन की तैयारी करें, आवश्यक सामान स्टॉक करें, और यात्रा से बचें।

पीला रंग

- पीला रंग सतर्क रहने की तरफ इशारा करता है। यह कोड संभावना जताता है कि मौसम की स्थिति कई दिन तक खराब बनी रह सकती है। मौसम बिगड़ने की वजह से लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में नियमित रूप से मौसम अपडेट्स लेने के साथ छोटी-छोटी सावधानियां भी जरूर बरतें।

नारंगी रंग

- नारंगी रंग का कलर-कोडेड अलर्ट अत्यधिक खराब मौसम की चेतावनी देता है। यह रंग सड़क, रेल, और हवाई यातायात में जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन सकती है। इसमें बाढ़, बिजली कटौती, यातायात पूरी तरह बंद, और बड़े पैमाने पर नुकसान शामिल हो सकता है। यह कोड सलाह देता है कि तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं, आपदा प्रबंधन निर्देशों का पालन करें, और गैर-जरूरी गतिविधियां बंद करें।

नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये नेचुरल चीजें

त्वचा की देखभाल के लिए बाजार में कई महंगे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन नेचुरल चीजों का कोई मुकाबला नहीं है। खासकर जब बात नारियल तेल की हो, तो सदियों से हमारे में घरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नारियल तेल में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ उसे चमकदार भी बनाते हैं। अगर आप नारियल तेल में कुछ घरेलू और असरदार चीजें मिलाकर इस्तेमाल करें, तो इसका प्रभाव और भी शानदार हो जाता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में, जिन्हें नारियल तेल में मिलाकर लगाने से त्वचा में जबरदस्त चमक आ सकती है।

हल्दी और नारियल तेल

हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीइफ्लेमेटरी गुण होते हैं। जब इसे नारियल तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है, तो यह त्वचा की गहराई से सफाई करता है और दाग-धब्बों को कम करता है। इसके लिए एक चुटकी हल्दी को एक चम्मच नारियल तेल में मिलाएं और 10-15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। बाद में गुनगुने पानी से धो लें।

शहद और नारियल तेल

शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है। नारियल तेल और शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर चेहरे पर लगाने से डेड स्किन हटती है। इसे 15 मिनट तक लगाकर रखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

नींबू का रस और नारियल तेल

नींबू में विटामिन C और ब्लीचिंग गुण होते है, जो त्वचा की रंगत निखारते हैं। अगर आपकी त्वचा ऑयली है और उस पर टैनिग या पिग्मेंटेशन है, तो नारियल तेल में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाकर लगाना फायदेमंद हो सकता है। ध्यान रखें कि नींबू का रस एसिडिक होता है, इसलिए इसे हफ्ते में 1-2 बार ही लगाएं और लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

चंदन पाउडर और नारियल तेल

चंदन पाउडर त्वचा को ठंडक पहुंचाने और दाग-धब्बे हटाने के लिए जाना जाता है। नारियल तेल में एक चम्मच चंदन पाउडर मिलाकर चेहरे पर पैस्ट की तरह लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक लगा रहने दें और सूखने के बाद धो लें। इसका नियमित इस्तेमाल से त्वचा में निखार आता है। एलोवेरा जेल और नारियल तेल नारियल तेल में बराबर मात्रा में एलोवेरा जेल मिलाकर लगाने से त्वचा को गहराई से नमी मिलती है, जिससे चेहरा ग्लोइंग और फ्रेश दिखता है। यह ड्राई और सेंसेटिव स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

सुशासन तिहार के सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाएः कलेक्टर दिव्या मिश्रा

समय सीमा की बैठक में आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कर आवेदकों को अनिवार्य रूप से सूचना देने को कहा

बालोद। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने राज्य शासन के द्वारा प्रदेश में एक मई से 10 जून के मध्य आयोजित की जाने वाली सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बालोद जिले में इसका सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दिव्या मिश्रा संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में दिव्या मिश्रा ने जिले में सुशासन तिहार के आयोजन के तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी विभाग प्रमुखों को सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने आवेदनों के निराकरण के पश्चात् आवेदकों को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, अजय किशोर लकरा एवं नूतन कंवर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने सुशासन तिहार के आयोजन के संबंध में राज्य शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक शिविरों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने अनुविभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी जनसमस्या निवारण शिविरों के नोडल अधिकारी होंगे। अनुविभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाले जन समस्या निवारण शिविर राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के नियंत्रण एवं देखरेख में संपन्न होगा।

32 जनसमस्या निवारण शिविर किया जाएगा

कलेक्टर ने कहा कि अपने-अपने अनुविभाग में आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविर के संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों की होगी। कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कुल 32 जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 23 एवं नगरीय क्षेत्रों में कुल 9 जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को शिविर में प्राप्त नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के प्रकरणों का त्वरित निराकरण के अलावा आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों का भी तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शिविर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इत्यादि हितग्राहीमूलक योजनाओं का पात्रतानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक अनुविभागों में 4 से 6 जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसका उन्होंने समुचित प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। जिससे कि आम जनता को सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविर की तिथि, स्थल एवं अन्य आवश्यक जानकारियां प्राप्त हो सके। कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत बालोद जिले में पहला जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन सोमवार 4 मई को डौण्डीलोहारा ब्लॉक के ग्राम पिनकापार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा।

शिविर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक किए जाएंगे आयोजित

कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं अन्य गणमान्य जनों के शिविर में प्रवास के दौरान वे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कलेक्टर ने सुशासन तिहार के दौरान आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक एवं प्रेस वार्ता के आयोजन के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले में अपने प्रवास के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट भी करेंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित होने वाली जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता एवं शर्तों आदि की जानकारी भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करने को कहा। कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने शिविरों में संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। इसके आधार पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा।

राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों के समीप प्याऊ घर स्थापित करने के निर्देश

बैठक में उन्होंने 11 मई को 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के आयोजन के संबंध में भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम का लाईव प्रसारण किए जाने की भी जानकारी दी। कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों का 'आई गोट मिशन कर्मयोगी' पोर्टल में आनबोर्डिंग के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्धारित तिथि तक जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से आनबोर्डिंग कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भीषण गर्मी को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों के समीप प्याऊ घर स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिलेवासियों के लिए पेयजल एवं निस्तारी हेतु समुचित मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए।

केनाल रोड निर्माण को 522.65 लाख की स्वीकृति, जल्द शुरू होगा कार्य

निगम और पीडब्ल्यूडी के समन्वय से तेज होगी निर्माण प्रक्रिया

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत जीई रोड से स्टेशन रोड को जोड़ने वाले साइंस कॉलेज के पीछे स्थित केनाल रोड के चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को 522.65 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

निविदा प्रक्रिया पूर्ण, शीघ्र जारी होगा कार्यादेश-निर्माण कार्य के लिए नगर निगम द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसे निविदा समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। वर्तमान में कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिससे कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सकेगा। नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग के समन्वय से कार्य प्रारंभ करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। विद्युत शिफ्टिंग एवं वृक्ष कटाई कार्य पूर्ण,परियोजना अंतर्गत विद्युत पोल शिफ्टिंग एवं इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य हेतु 25.89 लाख रुपये की राशि संबंधित विभाग को प्रदान की गई, जिसके तहत 33 केवी, 11 केवी एवं एलटी लाइन शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही वन विभाग को 6 लाख रुपये प्रदान कर वृक्ष कटाई का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित होगा केनाल रोड-परियोजना के अंतर्गत 380 मीटर लंबी एवं 15 मीटर चौड़ी बीटी सड़क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 0.30 मीटर चौड़ा डिवाइडर, 380 मीटर लंबी नई केनाल (जिसमें 320 मीटर खुली एवं 60 मीटर कवर) का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 16 दो-तरफा स्ट्रीट लाइट पोल एवं कॉलोनी एवं स्कूल के लिए 280 मीटर लंबा एप्रोच रोड भी विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आवागमन सुगम एवं सुरक्षित होगा।

आयुक्त का वक्तव्य-आयुक्त ने बताया कि साइंस कॉलेज के पीछे स्थित केनाल रोड निर्माण के लिए नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

निगम द्वारा पोल शिफ्टिंग एवं वृक्ष कटाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नहर शिफ्टिंग हेतु जल संसाधन विभाग से एनओसी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। नगर निगम एवं पीडब्ल्यूडी के समन्वय से शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

प्रोजेक्ट पर सदन की मुहर : पुराना बस स्टैंड और आयुर्वेदिक हास्पिटल टूटेगा, बनेगा कमर्शियल कांप्लेक्स

नगर निगम सामान्य सभा में मिली मंजूरी, लंबे समय से थी चर्चा , सदन में सात विषय लाए गए, सभी पर हुई चर्चा, हंगामा भी मचा

राजनांदगांव। मंगलवार को नगर निगम में सामान्य सभा हुई। सभा की शुरुआत से ही कांग्रेस के विपक्षी पार्षदों ने प्रापर्टी टैक्स में हुई बढ़ोतरी को लेकर हंगामा मचाया। सदन में 7 विषयों पर चर्चा हुई, देर शाम तक सभा चली। बड़ी बात यह देखने को मिली कि शहर के बीच बनने वाले नए प्रोजेक्ट्स को पास किया गया। इसमें पुराना बस स्टैंड के गांधी सभागृह, दुकानें और यात्री प्रतिक्षालय, गुढ़ाखू लाइन के पुराने औषधालय भवन और कस्तुरबा स्कूल से लगी निगम की दुकानों को तोड़ा जाएगा। साथ ही इन स्थानों पर व्यावसायिक कांप्लेक्स का निर्माण होगा। शहर के भीतरी इलाके पर इस बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। हालांकि पूर्व से ही इस पर चर्चा हो चुकी है। सामान्य सभा शुरू हुई, प्रश्नकाल चला। इसके बाद कांग्रेसी पार्षदों ने सत्ता पक्ष को प्रापर्टी टैक्स वृद्धि को लेकर घेरना शुरू कर दिया। पहले टैक्स पर बेतहासा बढ़ोतरी की गई, इस पर कांग्रेसियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं ने इसी विषय को लेकर महापौर मधुसूदन यादव से मिलकर चर्चा की। वहीं आम लोगों के बीच भी टैक्स को लेकर खलबली मची हुई थी। इस पर एक दिन पहले ही महापौर ने टैक्स को कम किया और उसमें 10 से 20 पीसदी की ही बढ़ोतरी की। यह आम लोगों से जुड़ा मुद्दा था, जिस पर सदन में काफी हंगामा भी मचा।

पात्रों को दुकानें भी दी जाएगी

जिन स्थानों को लेकर सदन में विषय लाया गया। वहां दुकानें भी जर्जर हो चुकी है, इसलिए उसे भी तोड़ा जाएगा। उन स्थानों पर दुकान भी लग रही है। ऐसे में यह भी साफकिया गया कि जो दुकानदार पात्र होंगे। उन्हें वहां जगह दी जाएगी। ताकि उन्हें कोई परेशानी का सामना न कर पड़े। क्योंकि पुराना बस स्टैंड में अब भी लोग व्यवसाय कर रहे है।

अवैध प्लाटिंग पर निगम की सख्त कार्रवाई, बाउण्ड्रीवाल ध्वस्त

भिलाईनगर। शहर को कब्जा मुक्त एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन एवं स्थानीय नागरिकों से मिली शिकायत के आधार पर निगम प्रशासन सक्रिय हुआ। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जोन-2 के राजस्व विभाग एवं बेदखली की संयुक्त टीम ने वार्ड क्रमांक 20 वैशाली नगर के बाबादीप सिंह नगर क्षेत्र में कार्रवाई की। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खाली जमीन पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। मुरूम डालकर प्लॉट काटे गए थे और बिना वैध अनुमति के उन्हें नागरिकों को बेचा जा रहा था। निगम की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध रूप से निर्मित बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया तथा मौके से संबंधित निर्माण सामग्री को जप्त किया गया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नागरिकों से अपीलः निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि की खरीद-फरोख्त से पहले उसके वैध दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी निगम को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

शहर की प्रथम नागरिक अलका बाघमार ने खुद भरा गणना पत्रक, शहरवासियों को जनगणना से जुड़ने का दिया संदेश

स्व-गणना अभियान में महापौर अलका बाघमार की पहल, परिवार संग सहभागिता कर लोगों को किया प्रेरित

दुर्ग। भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना की प्रक्रिया 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचालित की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत नगर निगम दुर्ग की प्रथम नागरिक महापौर अलका बाघमार द्वारा आज सुबह अपने परिवार की स्व-गणना कर नागरिकों को प्रेरित किया गया। जिसमे जिला अवसंरचना समन्वयक अमित कुमार ताम्रकार ने की प्रक्रिया को बताया नागरिकों की सुविधा के लिए स्व-गणना की व्यवस्था आधिकारिक पोर्टल पर 16 से 30 अप्रैल तक उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल, तेज एवं पारदर्शी बनेगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल में आसान भाषा में प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से भरकर नागरिक स्व-गणना आईडी प्राप्त कर सकते हैं। इससे जनगणना की प्रक्रिया को गति मिलेगी और समय पर कार्य पूर्ण हो सकेगा। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने आगे जानकारी दी कि स्व-गणना की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 1 मई से 31 मई तक प्रगणक घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे तथा जनगणना के कार्य को अंतिम रूप देंगे। नगर निगम दुर्ग द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्व-गणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और देश के इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वर्षा पूर्व सफाई अभियान तेज, नालों-नालियों की सफाई शुरू

वार्ड 51 सहित सभी वार्डों में नियमित सफाई, नहर सफाई भी जारी

दुर्ग। नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा वार्ड 51, साहू होटल के पास, घनोरा रोड, बोरसी में नाली की सफाई की गई है। इसके अलावा समस्त वार्डों में नालियों की नियमित सफाई की जा रही है। वर्षा ऋतु से पूर्व सभी बड़े नालों एवं नालियों की सफाई का कार्य प्रतिवर्ष वृहद स्तर पर किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी कार्ययोजना बनाकर सफाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही नहर सफाई का कार्य भी लगातार जारी है। इस संबंध में आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए समय रहते सभी नालों एवं नालियों की सफाई कराई जा रही है। मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे नालियों में कचरा न डालें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।

राशि सेंशन, बजट में शामिल लेकिन टेंडर अब तक नहीं, ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट थमने की हैट्रिक

एस्ट्रोटर्फ के लिए बीते नवंबर में तकरीबन साढ़े 6 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके

संस्कारधानी में अखिल भारतीय हॉकी स्पर्धा साल 2024 से अब तक नहीं हुई

राजनांदगांव। हॉकी की नर्सरी को तीन सालों से ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट नसीब नहीं है। जबकि नए एस्ट्रोटर्फ के लिए घोषणा हुई, पीडब्ल्यूडी के बजट में उसे शामिल कर लिया गया। लेकिन प्रसि5या अटकी हुई है। अभी टेंडर भी नहीं हो पाया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि साल 2026 की शुरुआत में टर्फ लगेगा और टूर्नामेंट होगा। लेकिन सरकारी काम की लचरता का नतीजा है कि खेल नगरी को इस बार भी नामचीन खिलाड़ियों के उम्दा खेल को देखने का मौका नहीं मिला। पिछले साल नवंबर 2025 में 6 करोड़ 40 लाख रुपए की घोषणा हुई। इसमें एस्ट्रोटर्फ के अलावा गैलरी और कुछ निर्माण होने थे। इसलिए तय माना गया कि आने वाले साल भी ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट आयोजित होगा। हॉकी संघ भी यही मान रहा था। लेकिन हुआ इसके उलट और प्रक्रिया कछुआ चाल में हुई। इस कारण टूर्नामेंट आयोजित नहीं हो पाया है। अभी भी नए साल का चार महीने बीत चुका है। अब तक टेंडर नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया होगा, लेकिन कब इसकी समय-सीमा तय नहीं है। इसके साथ ही खेलप्रेमियों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, यह भी देखना होगा।

एस्ट्रोटर्फ पर धब्बे , कई जगह से उखड़ भी गया

इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में लगा एस्ट्रोटर्फ पूरी तरह से खराब हो चुका है। कई जगह काले धब्बे पड़ गए हैं। इस कारण फिसलन भी होती हे। इसके अलावा टर्फ उखड़ने भी लगा है, जिसे टेप लगाकर काम चलाया जा रहा है। हॉकी की नर्सरी का मैदान इस दयनीय हालत में पहुंच जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। इस कारण शहर में कुछ जगहों पर हॉकी का अभ्यास चट मैदान पर कराया जा रहा है।

साल में कई आयोजन, फिर भी अनदेखी

साल में एक बार देशभर के बड़े खिलाड़ी यहां अपने खेल का प्रदर्शन करने आते हैं।
कई नामचीन टीमें यहां शिरकत करती है। इसके अलावा स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए लोकल लेवल पर टूर्नामेंट भी आयोजित होते हैं। लेकिन टर्फ खराब हो चुका है। ऐसे में खिलाड़ियों को दिक्कत आती है और चोट आने की भी आशंका रहती है। इसके बावजूद नए टर्फ को लेकर अनदेखी की जा रही है।

पावर हाउस चौक पर हटाया गया अवैध कब्जा, यातायात सुचारु करने की पहल

सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर निगम की सख्त कार्रवाई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में बढ़ते अतिक्रमण और यातायात अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जोन-3 अंतर्गत स्थित पावर हाउस चौक क्षेत्र में सड़क बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पावर हाउस चौक शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटे-बड़े एवं भारी वाहनों का आवागमन होता है। लगातार बढ़ते यातायात दबाव के बीच सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण ने स्थिति को और गंभीर बना दिया था, जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। निगम अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र के कुछ व्यापारी अपनी दुकानों के सामने सड़क तक सामान फैलाकर रखते हैं। वहीं फल एवं सब्जी विक्रेताओं द्वारा सड़कों पर ठेला लगाकर व्यवसाय संचालित किया जा रहा था। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो रही थी और यातायात बाधित हो रहा था, जिसके कारण जाम की स्थिति लगातार बन रही थी। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अतिक्रमण न केवल आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ाते हैं। विशेष रूप से व्यस्त समय में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की, ताकि आमजन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात की सुविधा मिल सके। निगम ने व्यापारियों और ठेला संचालकों से अपील की है कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें और केवल निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यवसाय संचालित करें। ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com